मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

मुंबई
वर्षः 9 अंक 20
शनिवार, 25 जुलाई 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

हर खबर निष्पक्षता के साथ

मॉनसून सत्रः संसद में गतिरोध जारी, पांचवें दिन भी कामकाज ठप, NEET पर बवाल

नई दिल्ली, 24 जुलाई। शुक्रवार को मॉनसून सत्र के पांचवें दिन संसद में बार-बार कार्यवाही स्थगित हुई और हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद NEET पेपर 'लीक' मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरी चर्चा की मांग कर रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और अब वे सोमवार सुबह 11 बजे फिर से मिलेंगे। वहीं, आज दोनों सदनों में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि वे NEET पेपर 'लीक' मामले पर लोकसभा में बहस होने दें। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई भी बहाना देश में गलत संदेश देगा। हालांकि, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जोर देना जारी रखा। पिछले पांच दिनों में लोकसभा में कोई खासी विधायी कामकाज नहीं हो सका तथा प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सके। सदन की बैठक शुक्रवार सुबह शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। इसके बाद सदन ने कारगिल संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।

श्रद्धांजलि के बाद विपक्षी सदस्य नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बाद में भी यह हंगामा जारी रहा जिसके बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजकर 13 मिनट पर सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा करने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों और इसका विरोध कर रहे सत्ता पक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण शुक्रवार को राज्यसभा की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उप सभापति हरिवंश ने कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन अधिनियम) विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है।

नीट पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन, एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त

नई दिल्ली, 24 जुलाई। नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और कुछ के खिलाफ कानूनी तथा आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह कदम उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय भेजे जाने के एक दिन बाद उठाया गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एनटीए में व्यापक बदलाव किए जाने की तैयारी है और आगे भी कई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। कम से कम 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और उनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी तथा आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।" प्रश्नपत्र लीक और सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन में आई गड़बड़ियों को लेकर पैदा हुए छात्रों के आक्रोश के कारण शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है।

प्रदर्शनकारी और विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर पेशेवर नियुक्तियों के एक समूह के लिए विज्ञापन जारी किए हैं और अलग से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के 'प्रतिभा सेतु पोर्टल' के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। अधिकारी ने कहा कि आने वाले कुछ हफ्तों में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार एनटीए के दस अलग-अलग कार्यक्षेत्रों में और लोगों की भर्ती की जायेगी।

जयराम रमेश ने शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार की नियुक्ति पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, 24 जुलाई। सीनियर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से कअर अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा सचिव नियुक्त करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव के तौर पर गंगवार के कार्यकाल के दौरान सब्सिडी से जुड़ी कथित अनियमितताओं का हवाला दिया है। पर एक पोस्ट में, रमेश ने सरकार की आलोचना की। यह आलोचना तब की गई जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि उसे NEET (UG) 2024 पेपर लीक मामले में संजीव कुमार (जिन्हें संजीव मुखिया के नाम से भी जाना जाता है) के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इन दोनों घटनाओं से NDA सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं।

रमेश ने लिखा कि पिछले 24 घंटों में हुई दो घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार की ईमानदारी पर और सवाल खड़े कर दिए हैं झ हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह एक ऐसे अधिकारी को लाया गया, जिनके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर कृषि मंत्रालय से भारी सब्सिडी ली थी, जबकि वे खुद पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय में शीर्ष अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे।

उन्होंने आगे कहा कि CBI ने संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी, जिसे पहले NEET-UG 2024 पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी ने पहले बिहार में विधानसभा चुनाव LJP के टिकट पर लड़ा था जो NDA का एक अहम सहयोगी दल है। NEET-UG पेपर लीक विवाद और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच, गुरुवार देर रात नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया।

जंतर-मंतर पर निगरानी को हाईकोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली, 24 जुलाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की कथित निगरानी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विस्तृत दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वीडियोग्राफी और चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने वीडियोग्राफी को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक वैध उपाय बताते हुए इसका बचाव किया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की आगे की सुनवाई सोमवार के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नंदिता राव ने नोटिस जारी करने की मांग की और तर्क दिया कि याचिका में उठाए गए मुद्दे 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शनों से संबंधित अन्य लंबित मामलों से अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए राव ने कहा कि सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेते समय भी नागरिकों को निजता का अधिकार प्राप्त है और इस अधिकार पर किसी भी प्रकार की रोक संवैधानिक वैधता, वैध राज्य उद्देश्य और आनुपातिकता की आवश्यकताओं को पूरा करनी चाहिए। राव ने कहा, पुट्टास्वामी मामले में कानून बहुत स्पष्ट है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सार्वजनिक स्थान पर, यहां तक कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भी, निजता का अधिकार है। इस पर रोक तभी लगाई जा सकती है जब राज्य त्रिगुण परीक्षण को पूरा करे। राव ने कहा कि यह याचिका विशेष रूप से पुलिस निगरानी से संबंधित है और इसे 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई से पहले ही दायर किया गया था।उन्होंने बताया कि याचिका में 16 से 20 वर्ष की आयु के छात्रों सहित युवा प्रदर्शनकारियों की कथित निगरानी का जिक्र है और उन्होंने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया था कि पुलिस वैन लाइव चेहरे की पहचान कर रही थीं।राव के अनुसार, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना चेहरे की पहचान तकनीक के कथित उपयोग से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी को अपराधीकरण का खतरा है। उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि राज्य वैध उद्देश्यों के लिए विरोध प्रदर्शनों को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग को नियंत्रित करने वाला कोई कानूनी ढांचा नहीं है। हम क्या मांग रहे हैं? कानून का ढांचा बनाएं। हमें दुरुपयोग से बचाएं। यहां तक कि फोन टैपिंग के लिए भी एक प्रोटोकॉल है, राव ने कहा, साथ ही यह भी जोड़ा कि ऐसी रिकॉर्डिंग को नियंत्रित करने वाला कोई डेटा सुरक्षा तंत्र नहीं है। संबंधित मामलों में से एक में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने राव के तर्कों का समर्थन किया और कहा कि पिछली याचिकाओं में निगरानी और निजता से संबंधित समान मुद्दे नहीं उठाए गए थे।

खालिस्तान समर्थक संगठन से जुड़ा अपराधी और अमेरिकी नागरिक नेपाल सीमा से गिरफ्तार

बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रूपईडीहा क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) एवं स्थानीय पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी संगठन 'वारिस पंजाब दे' से जुड़े एक वांछित अपराधी विक्रमजीत सिंह तथा अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह ढिल्लों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया है।

बहराइच के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के अजनाला थाने में 2023 के एक मामले में वांछित 'वारिस पंजाब दे' संगठन से जुड़ा विक्रमजीत सिंह कई दिनों से फरार था और पंजाब पुलिस को उसकी तलाश थी। उन्होंने बताया कि विक्रमजीत के साथ इसी संगठन से जुड़ा अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह ढिल्लों मूल रूप से पंजाब के मोगा का निवासी है और पंजाब पुलिस एक मामले में मनवीर को भी तलाश रही है।

श्रीवास्तव ने बताया कि शायद पुलिस की नजर में आने से बचने के लिए मनवीर ने भारत आने के लिए वीजा नहीं बनवाया था। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित रूपईडीहा सीमा चौकी पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय विक्रमजीत तथा मनवीर को पुलिस एवं एसएसबी ने रोककर पूछताछ की तो पुलिस को इनकी असलियत पता चली।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद से दिया इस्तीफा

बांग्लादेश, 24 जुलाई। बंगभवन के एक भरोसेमंद सूत्र ने एएनआई को बताया कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्र ने आगे बताया कि राष्ट्रपति के इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा बांग्लादेश के समय के अनुसार शाम 5:00 बजे की जाएगी। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, अगर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन इस्तीफा देते हैं, तो नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक संसद के स्पीकर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। इसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जातीय संसद के सदस्यों द्वारा नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। चूंकि नए राष्ट्रपति का कार्यकाल मौजूदा संसद से जुड़ा होगा, इसलिए अगला राष्ट्राध्यक्ष

कौन बनेगा, यह सवाल भी काफी अहम हो गया है।

मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 24 अप्रैल, 2023 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। उन्हें सत्ताधारी अवामी लीग के उम्मीदवार के तौर पर निर्विरोध चुना गया था। उनका पाँच साल का कार्यकाल अप्रैल 2028 में खत्म होने वाला था। यह आधिकारिक घोषणा बांग्लादेशी मीडिया में चल रही जबरदस्त अटकलों और बंगभवन में सत्ता के जल्द बदलाव के संकेतों के बाद की गई है।

स्थानीय समाचार माध्यमों की रिपोर्टों - जिनमें जमुना टीवी पर ब्रेकिंग अपडेट और दैनिक समाचार पत्र 'प्रोथोम आलो' की कवरेज शामिल है ने पहले ही संकेत दिया था कि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के पद छोड़ने की संभावना है, जिसकी वजह कथित तौर पर उनकी खराब सेहत बताई जा रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म '' पर यूके-स्थित बांग्लादेशी पत्रकार जुलकर्नाइन साएर के खुलासों के बाद इन राजनीतिक घटनाक्रमों ने और जोर पकड़ा।

साएर ने रिपोर्ट दी कि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन का जाना तय है और बताया कि कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी राष्ट्रपति पद के संभावित उत्तराधिकारियों की शॉर्टलिस्ट में शामिल हो गए हैं।

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37

* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
* चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
* विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध

TIWARI'S SARASWATI CLASSES
Since 1992
Parents' First Choice for 34+ Years
Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director
ADMISSIONS OPEN
9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE
NEET | JEE | MHT-CET
10 DAYS FREE DEMO
Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)
✓ 34+ Years of Academic Excellence
✓ Experienced & Dedicated Faculty
✓ Personal Attention
✓ Printed Notes & Regular Tests
✓ Strong Foundation for Boards & Competitive Exams
Santacruz Branch
101 Sai Chambers, Opp. Santacruz Railway Station (East), Near Depot, Santacruz (E), Mumbai 400055
Sion Branch
Opp. SIES College (Old), Near Gurukripa Hotel, Sion (West), Mumbai
Limited Seats / Small Batch Size
CALL NOW:
7738007373

NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE
2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Diamond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra
ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW

SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered
● Std. XI & XII (Sci.)
● NEET
● JEE (Main & Advance)
● MHT-CET
● Polytechnic & Engg
● Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)
M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

वैश्विक दवा उद्योग और भारत के लिए नई चुनौतियां

अशोक भाटिया

अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है. डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ-टैरिफ खेलने में खूब मजा आता है. अब अमेरिका ऐसा फैसला लेने जा रहा है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा. जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भारत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आयात होने वाली जेनेरिक दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 2028 से इम्पोर्ट की जाने वाली जेनेरिक दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया. इस फैसले से भारत की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका भारतीय दवा कंपनियों का सबसे बड़ा बाजार है. ट्रंप के इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारत के दवा उद्योग पर पड़ेगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर अगले दो साल तक कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा. यानी 2028 तक इन दवाओं पर आयात शुल्क शून्य रहेगा. लेकिन इसके बाद नियम पूरी तरह बदल जाएंगे. 2028 से एक साल के लिए इसे बढ़ाकर 100 परसेंट और फिर उसके बाद 200 परसेंट कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद ऐसी फार्मास्युटिकल दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में ही शुरू करना है. इस कदम से भारत पर असर पड़ सकता है. कारण कि अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है.

डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों का मूल मंत्र हमेशा से 'अमेरिका फर्स्ट' और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना रहा है। अपने पिछले कार्यकालों में उन्होंने ऑटोमोबाइल, स्टील और टेक सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन इस बार उनका निशाना देश की जीवनदायिनी स्वास्थ्य प्रणाली और दवा उद्योग पर है।इस कड़े कदम के पीछे ट्रंप प्रशासन के मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं जैसे सप्लाई चेन की आत्मनिर्भरता: कोविड-19 महामारी के दौरान अमेरिका ने महसूस किया था कि वह जीवन रक्षक दवाओं और उनके कच्चे माल के लिए चीन और भारत जैसे देशों पर अत्यधिक निर्भर है। ट्रंप इस रणनीतिक कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। घरेलू रोजगार का सृजन: जब विदेशी कंपनियां अमेरिका में अपने प्लांट स्थापित करेंगी, तो वहां अरबों डॉलर का निवेश होगा और अमेरिकी नागरिकों के लिए उच्च कुशल विनिर्माण क्षेत्र में लाखों रोजगार पैदा होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा: अमेरिकी नीति निर्माताओं का मानना है कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता एक राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम है। किसी भी भू-राजनीतिक तनाव या युद्ध की स्थिति में देश में दवाओं की भारी किल्लत हो सकती है।

गौरतलब है कि दुनिया भर में 'दुनिया की फामेर्सी' के रूप में मशहूर भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए यह फैसला एक बहुत बड़ा झटका है। भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। अमेरिकी बाजारों में बिकने वाली हर तीन में से एक जेनेरिक दवा किसी न किसी भारतीय कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इस नई नीति के लागू होने से भारतीय और वैश्विक दवा बाजार पर निम्नलिखित गंभीर प्रभाव पड़ेंगे जैसे अमेरिका में प्लांट लगाने का भारी दबाव: दो साल की 'शून्य टैरिफ' अवधि वास्तव में कोई बड़ी राहत नहीं बल्कि एक अंतिम चेतावनी है। भारतीय कंपनियों के पास केवल 24 महीने का समय है कि वे अमेरिका की धरती पर जमीन खरीदें, प्लांट लगाएं, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) से मंजूरियां लें और व्यावसायिक उत्पादन शुरू करें। जो कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएंगी, वे 100% और 200% टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार से पूरी तरह बाहर हो जाएंगी।लागत में भारी बढ़ोतरी: अमेरिका में जमीन, बुनियादी ढांचा, बिजली और सबसे महत्वपूर्ण 'लेबर' (श्रम) की लागत भारत की तुलना में कई गुना अधिक है। अमेरिका में दवा बनाने से कंपनियों की उत्पादन लागत (Cost of Production) आसमान छूने लगेगी, जिससे उनके मुनाफे के मार्जिन (Profit Margins) पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पूंजीगत व्यय (CapEx) का संकट: भारत की प्रमुख फार्मा कंपनियों (जैसे सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन और ऑरोबिंदो) को अमेरिकी धरती पर नए विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए अरबों डॉलर का भारी-भरकम निवेश करना होगा। इससे कंपनियों के कर्ज में बढ़ोतरी हो सकती है और घरेलू अनुसंधान एवं विकास के लिए उनके पास फंड की कमी हो सकती है।

ट्रंप प्रशासन का यह कदम जितना विदेशी कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण है, उतना ही यह खुद अमेरिकी नागरिकों और वहां की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए भी आत्मघाती साबित हो सकता है। जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि वे ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 80 से 90 प्रतिशत तक सस्ती होती हैं। इससे अमेरिकी सरकार के 'मेडिकेयर' और 'मेडिकेड' जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों का खर्च नियंत्रित रहता है। यदि विदेशी कंपनियां दो साल के भीतर अमेरिका में उत्पादन शुरू नहीं कर पाती हैं, तो आयातित दवाओं पर 100% से 200% टैरिफ लगने के कारण अमेरिका में दवाओं की कीमतें रातों-रात दोगुनी या तिगुनी हो जाएंगी। इसके विपरीत, यदि कंपनियां अमेरिका में उत्पादन शुरू भी कर देती हैं, तो वहां की उच्च विनिर्माण लागत के कारण दवाओं के दाम अंततः बढ़ेंगे ही। दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान अमेरिकी मरीजों का होगा, जिन्हें अपनी जेब से अधिक पैसे खर्च करने होंगे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस संक्रमण काल के दौरान अमेरिका में कई आवश्यक दवाओं की भारी किल्लत भी पैदा हो सकती है। हालांकि यह नीति सभी आयातित जेनेरिक दवाओं पर समान रूप से लागू होती है, लेकिन चीन और भारत के संदर्भ में इसके मायने अलग हैं। अमेरिका काफी समय से चीन से आने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) और दवाओं पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। चीन के साथ अमेरिका के भू-राजनीतिक संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं, इसलिए चीन के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे लगभग बंद होने जा रहे हैं। दूसरी ओर, भारत के साथ अमेरिका के संबंध रणनीतिक और व्यापारिक रूप से काफी मजबूत हैं। ट्रंप प्रशासन भारत को एक मित्र देश मानता है, लेकिन व्यापार घाटे के मामले में ट्रंप किसी को रियायत नहीं देते। भारत के लिए चुनौती यह है कि भारतीय कंपनियां स्वयं अपने कच्चे माल के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर हैं। ऐसे में यदि भारतीय कंपनियां अमेरिका में प्लांट लगाती भी हैं, तो उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति के लिए एक नया और सुरक्षित नेटवर्क तैयार करना होगा।

इस ऐतिहासिक संकट को भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग एक अवसर में भी बदल सकता है। इसके लिए भारतीय कंपनियों और भारत सरकार को मिलकर एक बहुआयामी रणनीति पर काम करना होगा जैसे अमेरिका में रणनीतिक अधिग्रहण : भारतीय कंपनियों को शून्य से नए प्लांट बनाने के बजाय अमेरिका में पहले से मौजूद बीमार या बंद पड़े विनिर्माण संयंत्रों को खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। इससे समय की बचत होगी और वे दो साल की समय-सीमा के भीतर उत्पादन शुरू कर सकेंगी। हाइब्रिड विनिर्माण मॉडल: कंपनियां दवाओं के फॉर्मूलेशन (तैयारी) का शुरूआती और सस्ता काम भारत में कर सकती हैं और उसकी अंतिम पैकेजिंग, फिनिशिंग और गुणवत्ता जांच अमेरिका में स्थापित प्लांट में कर सकती हैं, ताकि वे अमेरिकी नियमों के दायरे में आ सकें। नए बाजारों की खोज: भारतीय फार्मा उद्योग को अमेरिकी बाजार पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करना होगा। अब समय आ गया है कि भारत अफ्रीकी देशों, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में अपनी पैठ मजबूत करे। राजनयिक बातचीत भारत सरकार को अमेरिकी प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करनी चाहिए। भारत यह तर्क दे सकता है कि भारतीय जेनेरिक दवाएं अमेरिकी नागरिकों के स्वास्थ्य बजट को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। भारत को इस नीति में कुछ विशेष श्रेणियों की जीवन रक्षक दवाओं के लिए छूट या समय-सीमा को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने की मांग करनी चाहिए।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला वैश्विक मुक्त व्यापार के सिद्धांतों पर एक बड़ा आघात है और यह दशार्ता है कि आने वाले समय में वैश्विक व्यापार नीतियां कितनी संरक्षणवादी और आक्रामक होने वाली हैं। फार्मास्युटिकल सेक्टर, जिसे अब तक मानवीय आधार पर व्यापार युद्धों से दूर रखा जाता था, अब पूरी तरह से भू-राजनीति और आर्थिक राष्ट्रवाद के दायरे में आ चुका है।

भारतीय फार्मा उद्योग के लिए अगले दो साल 'करो या मरो' जैसे होने वाले हैं। यह समय केवल चिंता करने का नहीं, बल्कि अपनी रणनीतियों को नए सिरे से गढ़ने का है। यदि भारतीय कंपनियां अपनी परिचालन दक्षता, वैश्विक अनुभव और मजबूत वित्तीय स्थिति का सही इस्तेमाल करती हैं, तो वे अमेरिका की इस सख्त नीति के बावजूद न केवल अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बचाए रखने में सफल होंगी, बल्कि खुद को सच्चे अर्थों में एक बहुराष्ट्रीय और आत्मनिर्भर उद्योग के रूप में स्थापित कर सकेंगी। दुनिया की इस सबसे बड़ी स्वास्थ्य हलचल पर अब पूरे विश्व की नजरें टिकी हैं।

जल संकट का असंतुलित प्रबंधन: अस्तित्व पर मंडराता खतरा

-ललित गर्ग

जल केवल प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना असंभव है, फिर भी विडंबना यह है कि जिस जल को हमारी संस्कृति ने देवत्व प्रदान किया, उसी जल के प्रति हमारा व्यवहार सबसे अधिक लापरवाह रहा है। आज देश और दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों में जल संकट प्रमुख बन चुका है। बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध भूजल दोहन, जलवायु परिवर्तन और वर्षाजल के समुचित प्रबंधन के अभाव ने इस संकट को भयावह बना दिया है। यदि समय रहते चेतना नहीं जागी तो आने वाले वर्षों में पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सामाजिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और मानवीय संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हाल के शोध इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में उत्तर भारत का भूजल भंडार लगभग 450 घन किलोमीटर घट चुका है। यह मात्रा देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक इंदिरा सागर बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता से लगभग 37 गुना अधिक है। यह आंकड़ा केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि भविष्य के संकट का स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ है कि जिस भूजल पर करोड़ों किसानों की खेती और करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है, वह तेजी से समाप्त हो रहा है।

इस भयावह स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वर्ष 1951 से 2021 के बीच मानसूनी वर्षा में लगभग 8.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में सर्दियों का तापमान भी

बढ़ा है। तापमान में यह मामूली प्रतीत होने वाली वृद्धि भी मिट्टी की नमी को तेजी से कम करती है। परिणामस्वरूप खेतों को पहले की अपेक्षा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जब वर्षा कम होती है और सिंचाई की मांग बढ़ती है, तब किसान भूजल पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। यही कारण है कि भूजल का पुनर्भरण कम और दोहन अधिक हो रहा है। आज भारत के अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर हर वर्ष नीचे जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य भारत के कई हिस्से इस संकट की चपेट में हैं। अनेक स्थानों पर सैकड़ों फीट गहराई तक बोरवेल खोदने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। कई गांवों में हैंडपंप सूख चुके हैं और शहरों में टैंकर संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति बताती है कि यदि हमने अपनी जल नीति नहीं बदली तो आने वाले समय में पानी का संकट भोजन के संकट में भी बदल सकता है।

भारत की कृषि व्यवस्था आज भी लगभग 80 प्रतिशत मीठे जल का उपयोग करती है। दुर्भाग्य से धान, गन्ना जैसी अधिक पानी वाली फसलें उन क्षेत्रों में भी उगाई जा रही हैं जहां जल संसाधन सीमित हैं। मुफ्त बिजली और सस्ते पानी की नीतियों ने कई क्षेत्रों में अनियंत्रित भूजल दोहन को बढ़ावा दिया है। जल का मूल्य शून्य समझे जाने के कारण उसका संरक्षण भी नहीं हो पा रहा। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि नीति को जल उपलब्धता के अनुरूप बनाया जाए। जिन क्षेत्रों में पानी कम है, वहां मोटे अनाज, दालें, तिलहन तथा कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संकट केवल खेती तक सीमित नहीं है। उद्योगों, महानगरों और बढ़ते शहरी विस्तार ने भी भूजल पर अत्यधिक दबाव डाला है। बड़े-बड़े भवनों, कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षाजल सीधे नालों में बह जाता है। यदि प्रत्येक भवन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो जाए, तो लाखों लीटर पानी हर वर्ष धरती के भीतर पहुंच सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक राज्यों में कानून तो बने, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो पाया।

जल संकट का एक और गंभीर पक्ष जल प्रदूषण है। देश की अधिकांश नदियां औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कचरे और सीवेज के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं। जब नदियों और तालाबों का जल उपयोग योग्य नहीं रहता तो भूजल पर दबाव और बढ़ जाता है। इसलिए जल संरक्षण के साथ-साथ जल स्रोतों की स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है। नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी की जीवनरेखा है। यदि नदियां स्वस्थ रहेंगी तो भूजल भी समृद्ध होगा। आज आवश्यकता केवल नई परियोजनाओं की नहीं, बल्कि जल संस्कृति के पुनर्जागरण की है। भारत में कभी तालाब, बावड़ियां, जोहड़, कुंड और पारंपरिक जल संरचनाएं गांवों की पहचान होती थीं। ये वर्षा के जल को रोककर भूजल को समृद्ध बनाती थीं। आधुनिक विकास की दौड़ में इन जल स्रोतों को या तो नष्ट कर दिया गया या अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया। यदि इन पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन किया जाए तो जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

जल संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। घरों में पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकना, वर्षाजल संचयन अपनाना, रिसाव ठीक कराना, कम पानी वाले उपकरणों का उपयोग करना और बच्चों में जल संरक्षण के संस्कार विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक परिवार प्रतिदिन कुछ लीटर पानी भी बचाए तो राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों लीटर जल की बचत संभव है। सरकार को भी जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। प्रत्येक जिले के लिए भूजल बजट तैयार किया जाए, भूजल दोहन पर वैज्ञानिक नियंत्रण हो, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों-ड्रिप और स्प्रिंकलर-को व्यापक प्रोत्साहन मिले तथा ऐसे कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, जो कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित करे। साथ ही जल शिक्षा को विद्यालयों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जल के महत्व को केवल पुस्तकों में नहीं, व्यवहार में भी समझ सके। भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हमारे पास आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल बचेगा? यदि आज भी हमने जल को केवल उपभोग की वस्तु समझा तो आने वाले वर्षों में जल के लिए संघर्ष, पलायन और सामाजिक असंतोष बढ़ना स्वाभाविक होगा। खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आएगा। इसलिए जल संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक शांति का भी प्रश्न है। आज समय की पुकार है कि हम जल बचाना ही भविष्य बचाना है।हम बदलती जलवायु के अनुरूप अपनी नीतियों, कृषि प्रणाली और जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन लाने होंगे। वर्षा की प्रत्येक बूंद को धरती में उतारना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना और जल अनुशासन को जन-आंदोलन बनाना ही इस संकट का सबसे प्रभावी समाधान है। यदि सरकार, वैज्ञानिक, किसान, उद्योग, सामाजिक संगठन और आम नागरिक मिलकर इस दिशा में संकल्पबद्ध प्रयास करें तो जल संकट को अवसर में बदला जा सकता है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करना मानव सभ्यता की सबसे बड़ी विवशता बन जाएगा।

पेपर लीक पर छात्र आंदोलन से 2027 में राहुल-अखिलेश को कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा?

-अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान आंदोलन के बाद अब छात्र आंदोलन का मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नई राजनीतिक जमीन तैयार करता दिखाई दे रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा अब केवल परीक्षा केंद्रों और धरना स्थलों तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक पहुंच चुका है और विपक्षी दल इसे सरकार के खिलाफ बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या छात्रों का यह आक्रोश 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए वही चुनौती बन सकता है, जिसकी उम्मीद विपक्ष ने 2022 में किसान आंदोलन के बाद की थी ?इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सक्रियता सबसे अधिक दिखाई दे रही है। पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी पहले से सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन छात्रों के आंदोलन ने उन्हें सीधे सड़क पर उतरने का अवसर दे दिया है। अखिलेश यादव के लिए यह मुद्दा इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं की नाराजगी लंबे समय से विपक्ष के प्रमुख मुद्दे रहे हैं। छात्र आंदोलन को समर्थन देकर समाजवादी पार्टी एक ऐसे वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, जो आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।मामला केवल नीट या किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा रद्द होने, परिणाम में देरी और भर्ती प्रक्रिया पर उठते सवालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह समस्या और गंभीर हो जाती है, जहां लाखों युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। एक परीक्षा की तैयारी में परिवार की बचत, छात्र की उम्र और कई वर्षों का समय लग जाता है। ऐसे में परीक्षा रद्द होने या पेपर लीक की खबर केवल प्रशासनिक समस्या नहीं रहती, बल्कि परिवारों के लिए आर्थिक और भावनात्मक संकट बन जाती है।

केंद्र सरकार ने 2024 में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए कानून बनाया था। इस कानून में पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी को अपराध बनाया गया तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। इसके बावजूद जब लगातार नई घटनाओं को लेकर सवाल उठते हैं तो छात्रों का असंतोष स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यही वह बिंदु है जहां विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि कानून बनने के बाद भी व्यवस्था में वह भरोसा क्यों नहीं बन पाया, जिसकी छात्रों को सबसे ज्यादा जरूरत है।आंदोलन के बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देर रात वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक के खिलाफ और कड़े कदमों तथा नए कानून की बात करना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए गंभीर पीड़ा का विषय है और सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। सरकार की ओर से यह संदेश उस समय आया जब छात्र आंदोलन लगातार विस्तार ले रहा था और विपक्षी दल इसे संसद और सड़क दोनों जगह उठा रहे थे।यहीं से इस आंदोलन का राजनीतिक पहलू सामने आता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों जानते हैं कि छात्र आंदोलन को केवल सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल देना आसान नहीं है। छात्र किसी राजनीतिक दल के झंडे के नीचे आंदोलन शुरू नहीं करते। उनकी पहली मांग परीक्षा व्यवस्था में भरोसा, पारदर्शिता और भविष्य की सुरक्षा होती है। इसलिए विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह छात्रों की आवाज का समर्थन करते हुए आंदोलन पर अपना राजनीतिक कब्जा करने की कोशिश करता हुआ दिखाई न दे। 2022 का किसान आंदोलन इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में तीनों कानून वापस ले लिए थे। उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी भाजपा के खिलाफ बड़ा राजनीतिक माहौल बनाएगी। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया और जयंत चौधरी के साथ मिलकर किसान मुद्दे को चुनावी अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया।लेकिन चुनाव परिणामों ने विपक्ष की उम्मीदों को पूरी तरह सच साबित नहीं किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 255 सीटें जीतीं और उसके सहयोगियों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कुल सीटें 273 तक पहुंचीं। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिलीं, जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटें मिलीं। भाजपा का वोट प्रतिशत लगभग 41.29 प्रतिशत रहा, जबकि समाजवादी पार्टी को 32.06 प्रतिशत वोट मिले। यानी किसान आंदोलन के बाद भाजपा की सीटें जरूर घटीं, लेकिन वह सत्ता से बाहर नहीं हुई।हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदल दिया। समाजवादी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस के साथ गठबंधन ने भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस परिणाम ने विपक्ष को यह विश्वास दिया कि युवा, रोजगार, भर्ती और पेपर लीक जैसे मुद्दे यदि जातीय और सामाजिक समीकरणों से जुड़ जाएं तो भाजपा के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से एक साल पहले छात्र आंदोलन विपक्ष के लिए सामान्य विरोध प्रदर्शन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

लेकिन यहां किसान आंदोलन और छात्र आंदोलन के बीच बड़ा अंतर भी है। किसान आंदोलन मुख्य रूप से एक संगठित सामाजिक वर्ग और मजबूत किसान संगठनों के नेतृत्व में चला था। उसके पास गांवों तक फैला हुआ संगठनात्मक ढांचा था। छात्र आंदोलन का स्वरूप अधिक बिखरा हुआ है। इसमें अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा, कोचिंग संस्थानों से जुड़े छात्र, बेरोजगार अभ्यर्थी और उनके परिवार शामिल हैं। यह आंदोलन बहुत बड़ा जनभावनात्मक मुद्दा तो बन सकता है, लेकिन उसे चुनावी वोट में बदलना अपने आप में कठिन है।दूसरी चुनौती यह है कि छात्र हर चुनाव में एक जैसा राजनीतिक व्यवहार नहीं करते। एक ही परिवार में माता-पिता किसी एक दल के समर्थक हो सकते हैं, जबकि युवा किसी दूसरे दल के। कई छात्र रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से नाराज होने के बावजूद मतदान के समय कानून-व्यवस्था, जातीय समीकरण, कल्याणकारी योजनाओं, धार्मिक मुद्दों और स्थानीय उम्मीदवार को भी महत्व देते हैं। इसलिए यह मान लेना कि पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन सीधे भाजपा के वोट में बदल जाएगा, जल्दबाजी होगी।फिर भी इस आंदोलन को हल्के में लेना भाजपा के लिए जोखिम भरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का प्रभाव केवल उनके वोट तक सीमित नहीं रहता। वे अपने परिवारों और गांवों में राजनीतिक चर्चा को प्रभावित करते हैं। यदि लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक और भर्ती में देरी का मुद्दा बना रहता है तो यह सरकार के खिलाफ धीरे-धीरे जमा होने वाली नाराजगी में बदल सकता है।

राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा अवसर यही है कि वे इस आंदोलन को केवल सरकार विरोधी नारे तक सीमित न रखकर रोजगार, भर्ती कैलेंडर, परीक्षा सुरक्षा और जवाबदेही का ठोस राजनीतिक एजेंडा बनाएं। यदि विपक्ष केवल धरना, गिरफ्तारी और तस्वीरों तक सीमित रहा तो किसान आंदोलन की तरह छात्र आंदोलन का भी राजनीतिक लाभ सीमित रह सकता है। लेकिन यदि वह छात्रों की वास्तविक समस्याओं के समाधान का स्पष्ट मॉडल सामने रखता है, तो 2027 में यह मुद्दा भाजपा के खिलाफ व्यापक असंतोष को जोड़ने का काम कर सकता है।अंततः सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव छात्र आंदोलन से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। राजनीति में हर दल जनता के आंदोलनों से जुड़कर लाभ लेने की कोशिश करता है। असली सवाल यह है कि क्या छात्र उन्हें अपना विश्वसनीय प्रतिनिधि मानेंगे? किसान आंदोलन के बाद विपक्ष को उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिला था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश का मतदाता सत्ता के लंबे प्रभुत्व को भी चुनौती दे सकता है। अब 2027 में पेपर लीक और रोजगार का मुद्दा कितना बड़ा चुनावी हथियार बनेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार छात्रों का भरोसा कितनी जल्दी वापस हासिल करती है और विपक्ष आंदोलन की आवाज को कितनी गंभीरता से राजनीतिक कार्यक्रम में बदल पाता है। फिलहाल इतना साफ है कि छात्र आंदोलन केवल परीक्षा व्यवस्था का सवाल नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में यह अब सत्ता, विपक्ष और युवाओं के बीच भरोसे की लड़ाई बन चुका है।

डॉक्टर बनने की राह में संवेदनाएँ कहाँ खो जाती हैं?

- डॉ. सत्यवान सौरभ

देश में जब भी नीट परीक्षा होती है, उसके बाद केवल परिणामों की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की चर्चा शुरू हो जाती है। कभी पेपर लीक, कभी परीक्षा की पारदर्शिता, कभी आरक्षण, कभी कट-ऑफ और कभी लाखों विद्यार्थियों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को लेकर बहस छिड़ जाती है। हर वर्ष करोड़ों सपनों का भार इस एक परीक्षा पर टिका होता है। माता-पिता अपनी वर्षों की बचत दाँव पर लगा देते हैं, विद्यार्थी दिन-रात एक कर देते हैं और समाज उन सफल अभ्यर्थियों को भविष्य का जीवनरक्षक मानकर गर्व महसूस करता है।

लेकिन इन तमाम बहसों के बीच एक ऐसा प्रश्न है, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, फिर भी सबसे कम पूछा जाता है। आखिर यही बच्चे, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश करते हैं, उनमें से कुछ आगे चलकर ऐसे डॉक्टर क्यों बन जाते हैं जिनके व्यवहार को लेकर समाज में असंतोष दिखाई देता है? क्यों कभी-कभी मरीज को लगता है कि उसके सामने बैठा व्यक्ति पहले डॉक्टर नहीं, बल्कि एक व्यवसायी है? यह प्रश्न किसी पूरे चिकित्सक समुदाय पर आरोप नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की पड़ताल है जो एक संवेदनशील विद्यार्थी को कभी-कभी संवेदनहीन पेशेवर में बदल देती है।

यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि देश के अधिकांश डॉक्टर आज भी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और करुणा के साथ अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि हजारों चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा की। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के बीच कार्य करने वाले डॉक्टर आज भी चिकित्सा सेवा की गरिमा बनाए हुए हैं। इसलिए कुछ लोगों की गलतियों के आधार पर पूरे चिकित्सक समुदाय का मूल्यांकन करना अन्याय होगा। लेकिन यदि समाज में डॉक्टरों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है, तो उसके कारणों पर गंभीरता से विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। समस्या की शुरूआत मेडिकल कॉलेज से भी पहले हो जाती है। आज डॉक्टर बनने की तैयारी एक प्रतियोगी उद्योग बन चुकी है। कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को सफलता का अर्थ केवल रैंक, अंक और सीट समझाया जाता है। चिकित्सा को सेवा नहीं, बल्कि उपलब्धि और प्रतिष्ठा का माध्यम मानने की मानसिकता धीरे-धीरे विकसित होने लगती है। जब लक्ष्य केवल किसी भी कीमत पर मेडिकल सीट प्राप्त करना रह जाए, तब संवेदनशीलता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों की चर्चा पीछे छूट जाती है। इसके बाद यदि कोई छात्र अत्यधिक महँगे निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेता है, जहाँ शिक्षा पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये तक खर्च होते हैं, तो आर्थिक दबाव भी उसके भविष्य को प्रभावित करता है। कई परिवार कर्ज लेकर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह भावना जन्म लेती है कि अब इस निवेश की भरपाई करनी है। यह सोच चिकित्सा की मूल भावना के विपरीत है, लेकिन शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण ने इस मानसिकता को कहीं न कहीं जन्म दिया है। मेडिकल शिक्षा स्वयं भी अत्यंत कठिन है। वर्षों तक लगातार अध्ययन, इंटर्नशिप की लंबी ड्यूटी, रातभर जागकर काम करना, गंभीर मरीजों से रोज सामना होना, मानसिक तनाव और कई बार कठोर प्रशिक्षण—यह सब एक युवा छात्र के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यदि इस दौरान उसे भावनात्मक सहयोग, नैतिक चिकित्सा और मानवीय व्यवहार का पर्याप्त प्रशिक्षण न मिले, तो धीरे-धीरे मरीज एक इंसान नहीं, बल्कि एक ₹केस₹ बनकर रह जाता है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। एक-एक डॉक्टर को सैकड़ों मरीज देखने पड़ते हैं। सीमित संसाधनों, दवाओं की कमी और प्रशासनिक दबाव के बीच हर मरीज को पर्याप्त समय देना कई बार संभव नहीं होता। दूसरी ओर निजी अस्पतालों में कई स्थानों पर आय, पैकेज और लक्ष्य आधारित कार्य संस्कृति का दबाव रहता है। ऐसे माहौल में चिकित्सा सेवा और व्यापार के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। समस्या केवल डॉक्टरों की भी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा ढाँचा कई बार ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करता है जहाँ मानवीय संवेदनाएँ धीरे-धीरे थकने लगती हैं। लगातार तनाव, मुकदमों का डर, हिंसा की घटनाएँ, सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के आरोप और हर परिस्थिति में चमत्कार की अपेक्षा—ये सभी बातें डॉक्टरों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव डालती हैं। जब समाज और व्यवस्था दोनों किसी पेशे को लगातार तनाव में रखें, तो उसका असर व्यवहार पर पड़ना स्वाभाविक है। इसके बावजूद यह स्वीकार करना होगा कि कुछ डॉक्टरों द्वारा अनावश्यक जाँचें लिखना, कमीशन आधारित रेफरल देना, अत्यधिक शुल्क लेना या मरीज के साथ असम्मानजनक व्यवहार करना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। चिकित्सा केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि विश्वास का भी पेशा है। एक बार यदि यह विश्वास टूटता है तो उसकी भरपाई अत्यंत कठिन होती है। सबसे बड़ी कमी शायद हमारी चिकित्सा शिक्षा में नैतिक प्रशिक्षण की है। मेडिकल विद्यार्थियों को शरीर की संरचना, रोगों की पहचान और आधुनिक उपचार पद्धतियाँ तो विस्तार से पढ़ाई जाती हैं, लेकिन करुणा, संवाद, सहानुभूति और चिकित्सा नैतिकता को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती, जितनी मिलनी चाहिए। जबकि मरीज को सबसे पहले दवा नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। कई बार डॉक्टर का एक मधुर शब्द भी उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। नीट पर होने वाली बहस केवल परीक्षा की निष्पक्षता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि हमें वास्तव में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए तो मेडिकल शिक्षा को केवल ज्ञान और तकनीक तक सीमित रखने के बजाय उसे मानवीय मूल्यों से भी जोड़ना होगा। मेडिकल कॉलेजों में नैतिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा, ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर, संवाद कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को यह समझाना होगा कि चिकित्सा केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी है। सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, निजी मेडिकल शिक्षा की फीस को अधिक न्यायसंगत बनाने, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।

भिवंडी मनपा में श्रद्धापूर्वक मनाई गई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयंती

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। महाराष्ट्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार भिवंडी मनपा मुख्यालय में गुरुवार को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मनपा मुख्यालय के भूतल पर आयोजित कार्यक्रम में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मनपा के सहायक आयुक्त नितिन पाटिल तथा नगरसेविका श्रीमती रोमा नीलेश आलशी ने तिलक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके राष्ट्रनिर्माण और स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए अमूल्य योगदान को स्मरण किया। इस अवसर पर नगर सचिव अजय पाटिल, मुख्य उद्यान अधिकारी नीलेश संखे, प्रशासन अधिकारी सौदागर शिखरे, समाज कल्याण विभाग प्रमुख मिलिंद पलसुले, सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश आलशी सहित मनपा के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के आदर्शों पर चलने तथा राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पित रहने का संकल्प भी लिया गया।

दिव्यांग सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु 31 जुलाई तक ऑनलाइन करें आवेदन

पालघर(उत्तरशक्ति)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा वर्ष 2026 के दिव्यांग सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं नामांकन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जिला परिषद पालघर ने जिले के पात्र दिव्यांगजन, स्वयंसेवी संस्थाओं, नियोक्ताओं, कर्मचारियों तथा दिव्यांग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी डॉ. प्रकाश हसनालकर ने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल 15 मई 2026 से आवेदन के लिए खुला है। इच्छुक आवेदक https://awards.gov.in पोर्टल पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन करते समय निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक को अपने उल्लेखनीय एवं प्रेरणादायी कार्यों का विस्तृत विवरण तथा उनसे संबंधित प्रमाण एवं आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन, श्रेष्ठ दिव्यांगजन तथा श्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बालक/बालिका श्रेणियों में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए यूडीआईडी (वऊक्क) कार्ड अथवा दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। पुरस्कार की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य विस्तृत जानकारी https://depwd.gov.in और https://awards.gov.in पर उपलब्ध है। डॉ. प्रकाश हसनालकर ने जिले के सभी पात्र दिव्यांगजन, संस्थाओं एवं नियोक्ताओं से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 से पहले आवेदन कर अपने उत्कृष्ट कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर प्राप्त करें।

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुचारू हुआ उर्वरक कार्गो का संचालन

मुंबई। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला ने मौजूदा उर्वरक सीजन (फर्टिलाइजर सीजन) के दौरान उर्वरक कार्गो का बेहद कुशलतापूर्वक और प्रभावी प्रबंधन किया है। पोर्ट ने उर्वरक लाने वाले जहाजों के लिए दो विशेष बर्थ आवंटित किए हैं। इससे जहाजों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर ही बर्थ दिया जाना सुनिश्चित हुआ है, जिससे जहाजों का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है और उनके इंतजार का समय भी काफी कम हो गया है। पोर्ट द्वारा बनाए गए नए आधुनिक गोदामों से भंडारण क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। इससे माल के रखरखाव में आसानी हुई है और बंदरगाह पर भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिली है। रेलवे अधिकारियों ने भी माल की निकासी के लिए पर्याप्त रेक प्रदान करके उत्कृष्ट सहयोग दिया है। इसके परिणामस्वरूप, कांडला पोर्ट लगातार प्रति दिन औसतन 4.5 रेक लोड करने में सफल रहा है, जो इसकी उपलब्ध हैंडलिंग क्षमता के बिल्कुल अनुकूल है। पोर्ट अथॉरिटी, रेलवे प्रशासन, शिपिंग एजेंटों, स्टीवडोरों और सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों ने उर्वरक संचालन को निर्बाध बनाया है और माल की समय पर निकासी सुनिश्चित की है। इसका सीधा लाभ आयातकों, किसानों और संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मिल रहा है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष श्री सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में, पोर्ट ने परिचालन दक्षता बढ़ाने, जहाजों के टर्नअराउंड समय को कम करने और माल की आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से कई बुनियादी ढांचे और परिचालन संबंधी पहल की हैं। आधुनिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण, क्षमता विस्तार के उपायों और निरंतर प्रक्रिया में सुधारों ने उर्वरक प्रबंधन में पोर्ट की क्षमताओं को काफी मजबूत किया है।

संजय राउत का सवाल: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म क्यों? सरकार ने आंदोलन दबाया

मुंबई। शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने के तरीके पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों और आम जनता की मौजूदगी में खत्म होनी चाहिए थी। राउत ने वांगचुक के विरोध प्रदर्शन खत्म करने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन भूख हड़ताल खत्म कराने में केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका पर सवाल उठाए।

राउत ने कहा कि 26 दिनों तक चले इस आंदोलन ने देश के युवाओं और आम नागरिकों को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया। जिस सरकार के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसी सरकार के दो मंत्री भूख हड़ताल खत्म होने के समय वहां मौजूद थे। इससे कई सवाल उठते हैं। उन्होंने आगे पूछा कि सरकार ने वांगचुक को क्या भरोसा दिलाया था और जोर दिया कि इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस विरोध प्रदर्शन की मुख्य मांगों में से एक था, और राउत ने सवाल किया कि अगर यह मांग पूरी नहीं हुई, तो भूख हड़ताल खत्म करने की क्या वजह थी? राउत ने आरोप लगाया कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने पुलिस कार्रवाई के दौरान एक छात्र की मौत और कई अन्य लोगों के घायल होने पर चिंता जताई।

बाढ़ के पश्चात रिलायंस फाउंडेशन बना सहारा, हैंडपंपों की मरम्मत कर बहाल की स्वच्छ पेयजल आपूर्ति

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। पालघर जिले में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया था। बोरवेल और हैंडपंपों में बाढ़ का गंदा पानी व कीचड़ भर जाने से ग्रामीणों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में रिलायंस फाउंडेशन ने त्वरित पहल करते हुए राहत अभियान शुरू किया और प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था बहाल करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

रिलायंस फाउंडेशन की 15 सदस्यीय तकनीकी टीम ने कमारे, वाकसई और केलवा ग्राम पंचायत क्षेत्र के आदिवासी गांवों में पहुंचकर 15 हैंडपंपों की मरम्मत, सफाई तथा कीटाणुशोधन (डिसइन्फेक्शन) किया। इसके बाद कई दिनों से दूषित पानी की समस्या झेल रहे ग्रामीणों को फिर से सुरक्षित व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सका। यह पूरा अभियान स्थानीय प्रशासन के समन्वय से संचालित किया गया। राहत कार्य के साथ-साथ फाउंडेशन ने बाढ़ के बाद फैलने वाली जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए 'वॉश' (हअरत्न झ जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य) जागरूकता अभियान भी चलाया। इसके तहत चार विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें 100 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया।

कार्यक्रमों में विशेष रूप से महिलाओं को पेयजल को स्वच्छ रखने, सुरक्षित भंडारण, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा जलजनित रोगों से बचाव के प्रभावी उपायों की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने रिलायंस फाउंडेशन की इस त्वरित पहल की सराहना करते हुए कहा कि बाढ़ के बाद स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सबसे बड़ी आवश्यकता थी, जिसे फाउंडेशन ने समय रहते पूरा किया।

डोंबिवली में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

डोंबिवली (उत्तरशक्ति)। डोंबिवली में कांग्रेस की ओर से भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। बतादें की इंदिरा चौक परिसर में जिला अध्यक्ष अमित म्हात्रे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलन में स्कूल की छात्राएं भी शामिल हुईं और प्रदर्शन में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार जवाब दे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें।

जंतर-मंतर आंदोलन के समर्थन में भिवंडी में तिरंगा रैली, हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर किया विरोध प्रदर्शन

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को भिवंडी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली विधायक रईस शेख के नेतृत्व में शांतिनगर क्षेत्र में ‘एक देश, एक भावना’ के नारे के साथ निकाली गई रैली में हजारों की संख्या में युवक-युवतियों ने हाथों में तिरंगा लेकर भाग लिया और जंतर-मंतर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में तृतीयपंथी समुदाय के लोगों ने भी रैली में शामिल होकर प्रदर्शन किया। रैली में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की और अपनी नाराजगी व्यक्त की। रैली के कारण शांतिनगर क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए तथा यातायात को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया।

केसीएन क्लब द्वारा 26 जुलाई को निकाली जायेगी कारगिल पराक्रम जनजागृति मशाल पदयात्रा

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केसीएन क्लब एवं वेटरन्स भारत के संयुक्त तत्वावधान में रविवार 26 जुलाई 2026 को बोईसर में कारगिल पराक्रम जनजागृति मशाल पदयात्रा का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम के माध्यम से कारगिल युद्ध के वीर शहीदों एवं रणबांकुरों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी।

आयोजकों ने बताया कि इस प्रेरणादायी आयोजन का उद्देश्य युवाओं एवं आम नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना तथा देश के वीर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है। इस अवसर पर सभी देशभक्त नागरिकों, पूर्व सैनिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं एवं विद्यार्थियों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. एम. बी. सिंह चौहान (पूर्व सेना अधिकारी) होंगे, जबकि ब्रिगेडियर प्रदीप यदु (सेवानिवृत्त) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ सेना के अनेक वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक व गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ायेंगे। आयोजन के अनुसार कारगिल पराक्रम जनजागृति मशाल पदयात्रा सुबह 10:00 बजे प्रारंभ होकर दोपहर 12:30 बजे तक विभिन्न प्रमुख मार्गों से निकलेगी। यात्रा का शुभारंभ जिला परिषद स्कूल, नवापुर नाका, बोईसर से होगा तथा बृजवासी होटल, रेलवे स्टेशन, ओसवाल बस स्टैंड, मधुर होटल, अमेया पार्क होते हुए इच्छापूर्ति श्रीराम मंदिर हॉल, बोईसर में पहुंचकर सैनिक सम्मान एवं समापन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। आयोजकों ने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में कारगिल पराक्रम जनजागृति मशाल पदयात्रा में शामिल होकर कारगिल के अमर वीरों को श्रद्धासुमन अर्पित करने तथा राष्ट्र एकता का संदेश देने का आग्रह किया है।

अंधेरी में युवासेना की संगठनात्मक बैठक, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर दिया गया जोर

मुंबई (उत्तरशक्ति)। शिवसेना युवासेना (उद्धव) अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र की ओर से गुरुवार देर शाम अंधेरी (पूर्व) के पारसीवाड़ा स्थित शाखा क्रमांक-83 में संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को नई गति और दिशा देने के साथ बूथ एवं वार्ड स्तर तक उसे मजबूत बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक को संबोधित करते हुए युवासेना (उद्धव) अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विभाग अधिकारी अमेय रमेश लटके ने कहा कि पार्टी नेतृत्व की मंशा है कि आने वाले दिनों में विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ और वार्ड तक संगठन को सशक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी और संगठन को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी कार्यकताओं को सौंपी गई है, उस पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरा उतरना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी नेतृत्व का पूरा सहयोग कार्यकताओं को मिल रहा है।बैठक के दौरान युवासेना के कई पदाधिकारियों ने संगठन विस्तार, कार्यकताओं की सक्रिय भागीदारी और जनसंपर्क बढ़ाने को लेकर अपने सुझाव भी रखे।इस अवसर पर उप विभाग अधिकारी संदेश मोरे, जयेंद्र कूटे, अनिकेत छाछड़, शाखा अधिकारी मनीष नेरुलकर, समन्वयक प्रलेश सावंत, बैभव पवार सहित बड़ी संख्या में युवासेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

महेंद्र पाण्डेय ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक नियुक्त

मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा रोड वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रख्यात समाजसेवी श्री महेंद्र पाण्डेय को ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन का राष्ट्रीय संरक्षक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पर संस्था के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि महेंद्र पाण्डेय जैसे अनुभवी एवं समाजहित के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के संगठन से जुड़ने से संस्था को नई दिशा, नई ऊर्जा एवं सशक्त मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके संरक्षण में संगठन समाज सेवा के कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाएगा। ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती निशा तिवारी ने कहा, श्रेष्ठ नेतृत्व वही होता है जो समाज को सही दिशा दे, संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करे और सेवा के संकल्प को सशक्त बनाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि श्री महेंद्र पाण्डेय के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन समाजहित, राष्ट्रहित एवं जनकल्याण के कार्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचायगा। हम सभी उनके नेतृत्व में सेवा, संस्कार और संगठन की भावना को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महेंद्र पाण्डेय विगत कई वर्षों से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विशेष रूप से मीरा रोड क्षेत्र में उनके द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत कथा एवं अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रम समाज में आध्यात्मिक एवं सामाजिक जागरूकता का संदेश देते रहे हैं। ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन सदैव दीन-दुखियों, जरूरतमंदों एवं समाज के वंचित वर्गों की सेवा के लिए समर्पित रही है और भविष्य में भी सेवा, संस्कार एवं सामाजिक उत्थान के अपने संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी।

इस अवसर पर संस्था के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने महेंद्र पाण्डेय को राष्ट्रीय संरक्षक नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल एवं सफल कार्यकाल की मंगलकामनाएं व्यक्त कीं।

भिवंडी में मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा गुरु पूजा महोत्सव पर भव्य सत्संग एवं महाप्रसाद का आयोजन, श्रद्धालुओं ने लिया संतवाणी का लाभ

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। मानव उत्थान सेवा समिति, भिवंडी की ओर से कोंबडपाडा स्थित आर.आर. भवन सांस्कृतिक हॉल में गुरु पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य सत्संग, दिव्य प्रवचन एवं महाप्रसाद का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और संत महात्माओं के सत्संग का लाभ उठाया।

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 28 एवं 29 जुलाई को गाजियाबाद में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय गुरु पूजा महोत्सव के निमित्त भिवंडी में भी विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सद्गुरु श्री सतपाल जी महाराज के सैकड़ों अनुयायियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर गुरु महिमा का गुणगान किया तथा आध्यात्मिक वातावरण में भक्ति रस का अनुभव किया। इस अवसर पर महात्मा अंबालिका बाईजी, महात्मा कल्पना बाईजी, महात्मा आचार्य जी एवं रिंकी बहन जी सहित अन्य संत महात्माओं ने अपने प्रेरणादायी प्रवचनों में मानव जीवन में गुरु के महत्व, सत्संग की महिमा, प्रेम, सेवा, सदाचार और आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों पर प्रकाश डाला। संतों ने कहा कि सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है तथा समाज में प्रेम, सद्भाव और मानवता की भावना को मजबूत कर सकता है।

पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्ति गीतों और संतवाणी से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालु गुरु भक्ति में लीन होकर सत्संग का आनंद लेते रहे। प्रवचन के उपरांत सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से महाप्रसाद ग्रहण किया।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में मानव उत्थान सेवा समिति, भिवंडी के पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों का विशेष योगदान रहा। अंत में समिति की ओर से सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए आगामी गुरु पूजा महोत्सव में अधिक से अधिक लोगों से सहभागिता की अपील की गई।

फोर्स मोटर्स ने लॉन्च की नई अर्बानिया डीलक्स

मुंबई। भारत की सबसे बड़ी वैन निमार्ता और प्रमुख ऑटोमोटिव कंपनी फोर्स मोटर्स लिमिटेड ने आज अपनी नेक्स्ट-जनरेशन शेयर्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की एक नई प्रीमियम पेशकश अर्बानिया डीलक्स को लॉन्च किया। अर्बानिया प्लेटफॉर्म की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई अर्बानिया डीलक्स को यात्रियों के आराम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह बेहतर परफॉर्मेंस, प्रीमियम इंटीरियर और अत्याधुनिक तकनीक के साथ यात्रा का और भी शानदार अनुभव देगी। इस लॉन्च के साथ ही नई अर्बानिया डीलक्स मौजूदा अर्बानिया की जगह लेगी और प्रीमियम शेयर्ड मोबिलिटी सेगमेंट में फोर्स मोटर्स का मानक मॉडल बन जाएगी। फोर्स मोटर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रसन फिरोदिया ने कहा, अर्बानिया के जरिए हमने भारत में प्रीमियम शेयर्ड पैसेंजर मोबिलिटी को एक नई परिभाषा दी और एक नया वर्ग तैयार किया, जिसे भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी काफी पसंद किया गया। इसकी सफलता बेहतरीन आराम, सुरक्षा और आधुनिक इंजीनियरिंग का मेल पसंद करने वाले ग्राहकों की बढ़ती मांग को दर्शाती है। नई अर्बानिया डीलक्स को पेश करके हम इस प्लेटफॉर्म को बेहतर परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और एडवांस तकनीक के साथ अगले स्तर पर ले जा रहे हैं, ताकि अपने ग्राहकों की बढ़ती उम्मीदों को पूरा कर सकें और यात्रियों की मांग के मुताबिक उन्हें बेहतरीन सफर का अनुभव दे सकें। जैसे-जैसे प्रीमियम मोबिलिटी का दायरा बढ़ रहा है, हम अपने उत्पादों को बेहतर बनाने और ऐसे साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो यात्रियों के आराम, सुरक्षा और परफॉर्मेंस के नए मानक स्थापित करें। भारत के पहले पूरी तरह से स्क्रैच से बने मॉड्यूलर मोनोकॉक वैन प्लेटफॉर्म के रूप में पेश की गई अर्बानिया ने प्रीमियम शेयर्ड पैसेंजर मोबिलिटी के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं। इसने भारतीय बाजार में एक नया वर्ग तैयार किया है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए नई अर्बानिया डीलक्स कई नई खूबियां पेश करती है, जो इस सेगमेंट के ग्राहकों की बढ़ती उम्मीदों पर खरे उतरते हुए यात्रियों के सफर को और भी आरामदायक बनाती हैं, जो इस सेगमेंट के ग्राहकों की बढ़ती उम्मीदों पर खरे उतरते हुए यात्रियों के सफर को और भी आरामदायक बनाते हैं।

नई अर्बानिया डीलक्स में मर्सिडीज तकनीक पर आधारित 2.6 लीटर का 4-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन दिया गया है। यह शक्तिशाली इंजन 100 किलोवाट (134 एचपी) की पावर और 350 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिससे बेहतर पिकअप, आसान परफॉर्मेंस और शानदार ड्राइविंग अनुभव मिलता है। इसके केबिन को भी पूरी तरह अपग्रेड किया गया है, जिसमें लेदरेट सीट्स, मैचिंग अपहोल्स्ट्री और आकर्षक वुड-फिनिश फ्लोरिंग के साथ नया प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है, जो यात्रियों को बेहद आरामदायक माहौल प्रदान करता है। नई अर्बानिया डीलक्स में सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें हर यात्री के लिए कार जैसी 3-प्वाइंट सीट बेल्ट दी गई है। इसके साथ ही ड्राइवर और को-ड्राइवर एयरबैग्स, सभी पहियों में डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं।

ड्राइविंग अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए इसमें टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो वाहन की रीयल-टाइम जानकारी देता है।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय:
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाप हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामी: शरद फागुराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल स्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजुरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई - 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालय: मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्ल्यू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाप हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

पोस्टर में सानिया, काव्य लेखन में हिमांशी अव्वल

'विकसित भारत @2047' की परिकल्पना और 'माँ' की ममता रंगों व शब्दों में हुई साकार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के निदेशानुसार आयोजित दीक्षोत्सव

कार्यक्रमों की श्रृंखला में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान द्वारा 'विकसित भारत @2047' एवं 'मेरी माँ' विषय पर पोस्टर एवं काव्य लेखन प्रतियोगिता का आयोजन एस.पी. गुप्ता मेमोरियल लाइब्रेरी में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों एवं विभागों के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लेते हुए अपनी रचनात्मक प्रतिभा, कलात्मक अभिव्यक्ति एवं साहित्यिक संवेदनशीलता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने अपने पोस्टरों और कविताओं के माध्यम से विकसित भारत के सपनों, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका तथा माँ के प्रति सम्मान, प्रेम और समर्पण की भावनाओं को सशक्त अभिव्यक्ति दी।

पोस्टर प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. वनिता सिंह, डॉ. प्रियंका कुमारी, डॉ. शुभम सिंह एवं डॉ. आश्रेया दुबे ने किया। प्रतियोगिता में सानिया मौर्य (दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान) ने प्रथम, आशीष शैलेंद्र प्रजापति (बायोटेक्नोलॉजी विभाग) ने द्वितीय तथा खुशी सिंह (एमबीए-एचआरडी) एवं अंकुर मौर्य (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग) ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया।

काव्य लेखन प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. इंद्रजीत सिंह एवं डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने किया। इसमें हिमांशी श्रीवास्तव (बायोटेक्नोलॉजी विभाग) ने प्रथम, अनुराग यादव (फामेर्सी विभाग) ने द्वितीय तथा शशिकांत (दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. अनुराग मिश्र ने सभी प्रतिभागियों, निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 'इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिंतन, साहित्यिक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती हैं।

नवाब हुसैन गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प, स्वच्छता का दिया संदेश

कलापुर,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नवाब हुसैन गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज, कलापुर, जौनपुर में पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा स्वच्छ वातावरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में कॉलेज के प्रबंधक डॉ. आबिद खान एवं प्रधानाचार्या निकहत परवीन ने छात्राओं को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधे लगाने, जल का संरक्षण करने तथा प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का संकल्प लेना चाहिए।

इस अवसर पर छात्राओं ने पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने, अधिक से अधिक पौधे लगाने, प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने तथा जल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। शिक्षकों ने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे सकारात्मक प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में रहनुमा शेख, फातमा खान, इकरा शेख, हेबा शेख, रोकय्या शेख, सना शेख, जोया नशी, हमदा, लाडो, खुशी वर्मा, खुशी विश्वकर्मा, इलमा, फेजा वसी, आफिया खान एवं मुबस्सिरीन सहित अनेक छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यक्रम के अंत में सभी छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने तथा अपने आसपास स्वच्छ, हरित एवं प्रदूषणमुक्त वातावरण बनाए रखने का संकल्प लिया।

इस दौरान विद्यालय के लिपिक सुशील कुमार अस्थाना, शिक्षिकाएं बबीता, फायजा शेख, उज्मा खान,अरीबा सिद्दीकी, फिरदौस फातमा, बबिता,पूज प्रजापति,सविता, ऋषु सिंह, एवं रोशनी डिम्पल, शिक्षक राजाराम, सुमित अस्थाना, शिखर कुमार, अब्दुल रहमान, तथा मीडिया प्रभारी डॉ. इम्तियाज अहमद सहित विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

जिला अस्पताल में डीएम का औचक निरीक्षण, बंद ऑक्सीजन प्लांट और गंदगी पर भड़के

प्रियेश गुप्ता 'रुद्रा'

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी सैम्युल पाल एन ने गुरुवार को जिला अस्पताल

अधिकारियों को दिए सुधार के निर्देश

का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम के अचानक पहुंचने से अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

डीएम ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड, दवा वितरण व्यवस्था, मरीजों को मिल रही सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली।

निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर गंदगी और खराब साफ-सफाई व्यवस्था देखकर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और पूरे परिसर को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए। वहीं, करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट बंद मिलने पर डीएम ने गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) से प्लांट बंद होने का कारण पूछा और जल्द से जल्द इसे चालू कराने के निर्देश दिए।

अस्पताल भवन की तीसरी मंजिल पर जाने वाली जर्जर सीढ़ियों को देखकर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिला अस्पताल में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं में शीघ्र सुधार लाने के निर्देश दिए।

समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन के जिला कल्याण सचिव मुन्ना सिंह ने पद व सदस्यता से दिया इस्तीफा

सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन के जिला कल्याण सचिव मुन्ना सिंह ने अपने पद के साथ-साथ संगठन की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बी.यू. अंसारी को संबोधित त्यागपत्र भेजकर व्यक्तिगत, प्रशासनिक एवं व्यावसायिक कारणों का हवाला देते हुए संगठन से अलग होने का निर्णय लिया।

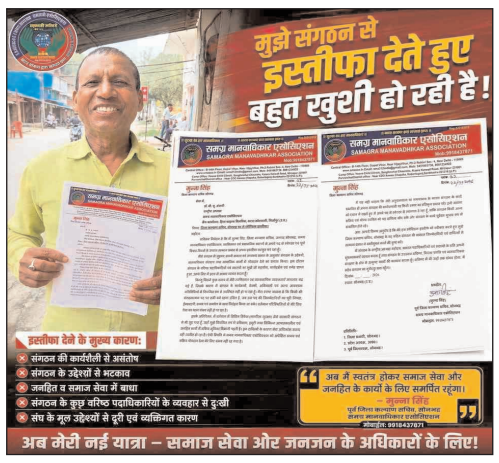

मुन्ना सिंह ने अपने त्यागपत्र में कहा कि संगठन से जुड़कर उन्हें मानवाधिकार संरक्षण और सामाजिक कार्यों में योगदान देने का अवसर मिला, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष, पदाधिकारियों और सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि बढ़ती व्यस्तताओं के कारण वे संगठन की बैठकों, अभियानों और अन्य गतिविधियों को अपेक्षित समय नहीं दे पा रहे थे।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में वे सिविल डिफेंस (नागरिक सुरक्षा) से जुड़े हैं, जहां नियमित प्रशिक्षण, ड्यूटी और जनहित से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहने के कारण संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना संभव नहीं हो पा रहा था। इसी कारण उन्होंने स्वेच्छा से पद और सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया।

त्यागपत्र में मुन्ना सिंह ने अनुरोध किया है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से संगठन के सभी दायित्वों से कार्यमुक्त किया जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में संगठन की किसी भी बैठक, कार्यक्रम, अभियान, सदस्यता अभियान या चंदा संग्रह के लिए उन पर किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए।

उन्होंने संगठन के उज्ज्वल भविष्य और मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर बेहतर कार्यों के लिए शुभकामनाएं भी दीं। समाचार लिखे जाने तक समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन की ओर से उनके इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई थी।

जातिसूचक टिप्पणियों के विरोध में एसबीएसपी का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी)

के कार्यकर्ताओं ने जातिसूचक एवं अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित एवं आदिवासी समाज के सम्मान, सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से जातिसूचक और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। एसबीएसपी ने ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।

पार्टी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे कथित आपत्तिजनक कंटेंट पर भी प्रभावी कार्रवाई करने और वंचित वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर संबंधित मामलों में निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए।

एसबीएसपी पदाधिकारियों ने कहा कि सभी वर्गों के सम्मान और सामाजिक सद्भाव की रक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण या अपमानजनक टिप्पणी पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

अवैध असलहे के साथ युवक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस जांच में जुटी

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिले में एक युवक की कथित रूप से अवैध असलहे के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल फोटो को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चचाएँ हो रही हैं।

सूत्रों के अनुसार, युवक सोशल मीडिया पर असलहे के साथ तस्वीरें पोस्ट कर क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। वायरल पोस्ट के आधार पर युवक की पहचान अमित कुमार पुत्र पप्पू कुमार, निवासी ग्राम मेहौड़ा, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर के रूप में बताए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, उत्तरशक्ति इस वायरल फोटो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। मामले की सत्यता एवं फोटो में दिखाई दे रहे असलहे की वैधता की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।

पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी व मोबाइल छिनैती गिरोह का किया पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सुजानगंज थाना पुलिस ने ई-रिक्शा

चोरी और मोबाइल छिनैती की दो घटनाओं का सफल खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक चोरी का मालवाहक ई-रिक्शा और चार एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी बदलापुर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अमित कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बारा पंचरास्ता से चौबेपुर नहर रोड के पास घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवम यादव (19), रोहित सोनी (19), कुलदीप सिंह (20) और अमन सरोज (22) के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद पुलिस ने इनके कब्जे से एक मालवाहक ई-रिक्शा तथा चार एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए।

पुलिस के अनुसार आरोपी थाना सुजानगंज में दर्ज ई-रिक्शा चोरी एवं मोबाइल छिनैती के मुकदमों में वांछित थे। चारों आरोपियों के खिलाफ सुजानगंज और बदलापुर थानों में पूर्व से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष अमित कुमार पाण्डेय, उपनिरीक्षक रामभवन यादव, उपनिरीक्षक सुभाषचंद्र द्विवेदी सहित थाना सुजानगंज की पुलिस टीम की प्रमुख भूमिका रही।

एसएसपी ने पुलिस कार्यालय में की जनसुनवाई, शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुँवर अनुपम सिंह ने गुरुवार को पुलिस कार्यालय में प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई कर फरियादियों की समस्याएं और शिकायतें सुनीं। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें एसएसपी के समक्ष प्रस्तुत कीं। एसएसपी ने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान पुलिस की प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि फरियादियों को शीघ्र न्याय मिल सके।

मालगाड़ी की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत, शव के हुए कई टुकड़े

खेतासराय,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। खेतासराय रेलवे स्टेशन के समीप कासिमपुर स्थित रेलवे पोल संख्या 853 के पास गुरुवार को मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मृतक के शव के कई टुकड़े रेलवे ट्रैक पर बिखर

गए। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रेलवे ट्रैक पर व्यक्ति के मालगाड़ी से कटने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने रेलवे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव के क्षत-विक्षत अवशेषों को एकत्र कर कब्जे में ले लिया।

पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र लगभग 35 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक उसकी पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने बताया कि पहचान होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान को लेकर डीएम ने दिए सख्त निर्देश, साफ-सफाई और फॉगिंग पर जोर

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान को लेकर अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अभियान से जुड़ी सभी गतिविधियों को निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार समय से पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने पंचायती राज विभाग को सभी ग्राम पंचायतों में झाड़ियों की कटाई, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और साफ-सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में नियमित फॉगिंग एवं एंटीलार्वा रसायन का छिड़काव कराने को कहा।

उन्होंने नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों के सभी वार्डों और मोहल्लों में विशेष सफाई अभियान चलाने, फॉगिंग कराने तथा मच्छरों के नियंत्रण के लिए एंटीलार्वा रसायन का छिड़काव कराने के निर्देश दिए।

बैठक में पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया कि शूकर पालकों को साफ-सफाई बनाए रखने, कीटनाशी रसायन का छिड़काव कराने और शूकरों को खुले में न छोड़ने के लिए जागरूक किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी ब्लॉकों में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा शत-प्रतिशत भ्रमण कराया जाए, लक्षणयुक्त मरीजों की पहचान की जाए और लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने दवाओं, जांच किट, प्लेटलेट्स सहित आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डीएम ने डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए सभी तैयारियां पूरी रखने तथा स्कूल-कॉलेजों में साफ-सफाई, झाड़ियों की कटाई और छात्र-छात्राओं को संक्रामक रोगों से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खड़िया, अपर एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी वीबीडी, जिला मलेरिया अधिकारी, समस्त अधीक्षक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

दीक्षोत्सव में खेल प्रतिभाओं का दमदार प्रदर्शन

◆ विजेता खिलाड़ियों को कुलपति ने किया सम्मानित

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांतपूर्व दीक्षोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को परंपरागत खेल प्रतियोगिताओं का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। रस्साकशी एवं कबड्डी प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों एवं विभागों के छात्र-छात्राओं ने पूरे जोश और खेल भावना के साथ भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं के समापन पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने विजेता टीमों को सम्मानित किया।

महिला रस्साकशी प्रतियोगिता में एम.एससी. माइक्रोबायोलॉजी की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बी.एससी. बायोटेक्नोलॉजी (ऑनर्स) की टीम उपविजेता रही, जबकि बी.एससी. जेडबीसी की टीम ने तृतीय स्थान हासिल किया।

पुरुष रस्साकशी प्रतियोगिता में बीसीए की टीम विजेता बनी। एम.एससी. माइक्रोबायोलॉजी की टीम द्वितीय तथा बी.एससी. बायोटेक्नोलॉजी (ऑनर्स) की टीम तृतीय स्थान पर रही।

महिला कबड्डी प्रतियोगिता में बी.एससी. जेडबीसी की टीम ने प्रथम, एम.एससी. माइक्रोबायोलॉजी की टीम ने द्वितीय तथा बी.एससी. बायोटेक्नोलॉजी (ऑनर्स) की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में बीसीए की टीम विजेता घोषित हुई।

पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने सभी विजेता एवं प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास का सशक्त माध्यम हैं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना का भी विकास करते हैं। अंत में उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं।

कार्यक्रम के संयोजक प्रो. प्रदीप कुमार के निर्देशन में आयोजित प्रतियोगिताओं एवं पुरस्कार वितरण समारोह में खेल विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, रजनीश, राजेश, शिक्षक डॉ. संजीव मौर्य, डॉ. ईशानी भारती, डॉ. ऋषि श्रीवास्तव, डॉ. विवेक सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

सौ. कंचन झा बनीं महाराष्ट्र भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष संध्या दुबे गर्ग, तृप्ति शरद मामले और राजल नाईक बनीं प्रदेश सचिव

वसई रोड। वसई-विरार की पूर्व भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सौ. कंचन झा पोद्दार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। उनकी नियुक्ति पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

इसके साथ ही संध्या दुबे गर्ग, तृप्ति शरद मामले और राजल नाईक को भाजपा महिला मोर्चा का महाराष्ट्र प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती और जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि इन नई जिम्मेदारियों के साथ महिला मोर्चा का संगठन प्रदेशभर में और अधिक सशक्त होगा तथा महिलाओं के सशक्तिकरण और जनहित के कार्यों को नई गति मिलेगी। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया और उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।

पुष्यमित्र भार्गव ने सीवर लाइन शिफ्टिंग का किया भूमि पूजन

इंदौर (उत्तरशक्ति)। इंदौर में चंद्रशेखर आजाद चौराहे पर प्रस्तावित ब्रिज निर्माण की तैयारियों के तहत महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने चंदन नगर तिराहे पर एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत से होने वाले सीवर लाइन शिफ्टिंग कार्य का भूमिपूजन किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि आप सब से मेरा वादा है कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का यह अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहे रहेगा। यह जानकारी दैनिक उत्तर शक्ति समाचार पत्र के चीफ ब्यूरो प्रणित नरेंद्र तिवारी ने दी है।

आजमगढ़: फर्जी खतौनी के आधार पर जमीन बेचने का ठगी करने वाले गिरोह का हुआ पदार्फाश, चार गिरफ्तार

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। अहरौला पुलिस ने शुक्रवार को फर्जी खतौनी के आधार पर जमीन बेचने का झांसा देकर 35 लाख रुपये की ठगी करने वाले चार सदस्यीय गिरोह का पदार्फाश किया। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड शोभनाथ सेठ समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त एक कार और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी शोभनाथ सेठ के खिलाफ एनआई एक्ट के 20 से अधिक मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि अहरौला पुलिस को सूचना मिली कि थाना अहरौला में दर्ज धोखाधड़ी के प्राथमिकी से जुड़े आरोपी बरामदपुर पुलिया की ओर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार को रोककर तलाशी ली। इसके बाद अहरौला थाना क्षेत्र के मतलूबपुर निवासी शोभनाथ सेठ, सुधीर सेठ, इन्द्रभूषण सेठ और दनियालपुर निवासी मुन्नीलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे फर्जी एवं कूटरचित खतौनी दिखाकर लोगों को जमीन बेचने का झांसा देते थे। भरोसा जीतने के बाद बैंक खाते में आरटीजीएस और नकद के माध्यम से रुपये ले लेते थे, लेकिन न तो जमीन का बैनामा कराते थे और न ही रकम वापस करते थे। रुपये मांगने पर पीड़ितों के साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। इस मामले में अतरौलिया थाना क्षेत्र के दुर्गेश कुमार पांडेय की तहरीर पर थाना अहरौला में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी शोभनाथ सेठ और उसके भाई सुधीर सेठ के खिलाफ पूर्व में भी धोखाधड़ी सहित कई प्राथमिकी दर्ज हैं। शोभनाथ सेठ के विरुद्ध एनआई एक्ट के 20 से अधिक मामले भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। पुलिस आरोपियों के अन्य मामलों और ठगी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

गाजीपुर: गंगा नदी में डूबने से दो मासूमों की मौत,

गाजीपुर (उत्तरशक्ति)। करंडा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा माहेपुर निवासी कृष्णा बिंद (साढ़े तीन वर्ष) व प्रिया बिंद (5) की गंगा में डूबने से मौत हो गई। घटना शुक्रवार की सुबह साढ़े सात बजे के आसपास की है। मृतक बच्चे संतोष बिंद के है। बच्चे सुबह घूमते हुए गंगा नदी किनारे गये थे। कुछ लोंगो ने उन्हें वहां देखा तो वापस जाने को कहा था। बच्चे पुनः घूमकर गंगा नदी किनारे गये और नदी में उतर गये। डूबते बच्चों को दूर खड़े आदमी ने देख कर शोर मचाया, जब तक लोग वहां पहुंचते तब तक दोनों बच्चे डूब गए थे। बच्चों का शव गंगा नदी से निकाल लिया गया। पुलिस ने शव को लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर अब्बोपुर में होगा सामाजिक न्याय एवं धार्मिक एकता सम्मेलन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर 25 जुलाई को शाम 4 बजे जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अब्बोपुर में सामाजिक न्याय एवं धार्मिक एकता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन वीरांगना फूलन देवी सामाजिक न्याय मंच द्वारा किया जा रहा है।

वीरांगना फूलन देवी सामाजिक न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक न्याय, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव तथा संविधान में निहित समानता और न्याय के मूल्यों को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ फूलन देवी के नाम अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर 200 पौधों का रोपण एवं वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक चेतना को साथ लेकर चलना समय की आवश्यकता है और यह अभियान उसी दिशा में एक सार्थक पहल है। मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि वीरांगना फूलन देवी भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय की एक महत्वपूर्ण आवाज थीं। उन्होंने वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा संसद में उनकी आवाज को मजबूती से उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी आंदोलन के पुरोधा एवं पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने फूलन देवी के विरुद्ध लंबित मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई, जिससे उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ। बाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें राजनीति में आने का अवसर दिया और उन्होंने वर्ष 1996 एवं 1999 में मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए वंचित समाज के मुद्दों को संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि वीरांगना फूलन देवी के संघर्ष, साहस, सामाजिक न्याय और समानता के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुँचाया जाए तथा समाज में प्रेम, भाईचारे और धार्मिक एकता को और मजबूत किया जाए। मंच ने जौनपुर सहित आसपास के जनपदों के सामाजिक संगठनों, युवाओं, किसानों, महिलाओं एवं सर्वसमाज के लोगों से सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने तथा एक पेड़ फूलन देवी के नाम अभियान में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की है।

छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व संतुष्टि शिविर में शामिल हुई विधायक स्नेहा दुबे पंडित

वसई। वसई पश्चिम स्थित जी.जी. कॉलेज में महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग द्वारा आयोजित 'छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व संतुष्टि शिविर' का उद्घाटन वसई विधायक स्नेहा दुबे पंडित एवं राज्य स्तरीय आदिवासी विकास समीक्षा समिति के अध्यक्ष (मंत्री स्तर) विवेक भाऊ पंडित ने संयुक्त रूप से किया। यह शिविर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत दादा पवार की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। इसके बाद उप-विभागीय अधिकारी एवं उप-विभागीय मजिस्ट्रेट शेखर घाडगे ने शिविर के उद्देश्य, नागरिकों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने की पहल तथा अभियान की रूपरेखा की जानकारी दी।

इस अवसर पर विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सुशासन के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार नागरिकों को उनके अधिकार उनके द्वार तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल योजनाओं का लाभ वितरण नहीं, बल्कि नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने का अभियान है। उन्होंने अधिकारियों से वसई तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित करने की अपील की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विवेक भाऊ पंडित ने पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत दादा पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा अभियान को सफल बनाने में जुटे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग राज्य शासन की रीढ़ है और विभिन्न विभागों को एक मंच पर लाकर नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्यभर में चल रहे इस अभियान के तहत अब तक 1,588 भूमिहीन किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया जा चुका है, हालांकि अभी भी कई लोगों तक अधिकार पहुंचाना बाकी है।

उन्होंने वन भूमि पर बसे गांवों के नियमितीकरण एवं वनाधिकार कानून, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर देते हुए कहा कि सरकार नागरिकों और प्रशासन के बीच की दूरी कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

शिविर में राजस्व विभाग के साथ-साथ नगर निगम, कृषि, मत्स्यपालन सहित विभिन्न विभागों द्वारा नागरिकों को अनेक सरकारी सेवाएं और योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई।

इस अवसर पर उप-विभागीय अधिकारी एवं उप-विभागीय मजिस्ट्रेट शेखर घाडगे, तहसीलदार दीपक गायकवाड़, जिला भूमि अभिलेख विभाग के उप-अधीक्षक अमोल बड्डे, नगरसेविका निम्मी निपुण दोशी, पिंकी राठौड़, फादर अनिल परेरा, प्रोफेसर विभूते, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

वाराणसी : कैंट स्टेशन पर 1.95 करोड़ की ज्वेलरी बरामद, दो युवक हिरासत में; आयकर विभाग ने शुरू की जांच,

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। कैंट स्टेशन पर 1.95 करोड़ की ज्वेलरी बरामद, दो युवक हिरासत में; आयकर विभाग ने शुरू की जांच वाराणसी (रणभेरी): कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने नियमित चेकिंग अभियान के दौरान दो युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़कर उनके कब्जे से करीब 1.95 करोड़ रुपये मूल्य की सोने और हीरे की ज्वेलरी बरामद की है। दोनों युवक आभूषणों से जुड़े कोई वैध दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद जीआरपी ने आयकर विभाग को सूचना देकर मामले की जांच शुरू करा दी। जानकारी के अनुसार, जीआरपी की टीम शनिवार को कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर गश्त के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान अलग-अलग स्थानों पर मौजूद दो युवक पुलिस को संदिग्ध दिखाई दिए। जब उनसे पूछताछ की गई तो वे अपने आने-जाने और सामान के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके। संदेह बढ़ने पर दोनों को जीआरपी थाने लाकर उनके बैग की तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान बैग से बड़ी मात्रा में सोने और डायमंड के आभूषण बरामद हुए। पुलिस ने जब इन आभूषणों के खरीद-बिक्री या परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे तो दोनों युवक कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए। बरामद ज्वेलरी की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 95 लाख रुपये आंकी गई है।

वाराणसी कैंट स्टेशन पर 1.95 करोड़ की ज्वेलरी बरामद, दो युवक हिरासत में; आयकर विभाग ने शुरू की जांच जीआरपी थाना प्रभारी रजोल नागर ने बताया कि पूछताछ में दोनों युवकों ने अपनी पहचान गुजरात के सूरत निवासी रौनक और गौतम के रूप में बताई है। उनका कहना है कि वे यह ज्वेलरी सूरत से लेकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जा रहे थे। हालांकि जौनपुर में यह आभूषण किसे सौंपे जाने थे और इसका वास्तविक कारोबारी नेटवर्क क्या है, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी ने तत्काल आयकर विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम कैंट स्टेशन पहुंची और दोनों युवकों से पूछताछ शुरू कर दी। अधिकारियों द्वारा बरामद आभूषणों की वैधता, स्वामित्व, परिवहन और टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

जीआरपी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि आभूषणों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं या जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।फिलहाल जीआरपी और आयकर विभाग संयुक्त रूप से पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि बरामद ज्वेलरी किसी वैध व्यापारिक लेन-देन का हिस्सा थी या इसके पीछे कोई अन्य नेटवर्क सक्रिय है।

जितेंद्र सिंह बने भाजपा मुंबई उत्तर पश्चिम जिला के उपाध्यक्ष

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी मुंबई ने संगठनात्मक विस्तार के तहत समाजसेवी जितेंद्र सिंह को उत्तर पश्चिम जिला का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। भाजपा नेतृत्व ने विश्वास जताया है कि उनके अनुभव और सक्रिय कार्यशैली से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। भाजपा मुंबई अध्यक्ष विधायक अमित साटम के नेतृत्व, विधायक विद्या ठाकुर के मार्गदर्शन तथा भाजपा मुंबई महामंत्री आचार्य पवन त्रिपाठी की प्रेरणा से यह नियुक्ति की गई। भाजपा उत्तर पश्चिम जिला प्रभारी राजेश शिरवडकर और जिला अध्यक्ष एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा ने जितेंद्र सिंह को नियुक्ति पत्र सौंपकर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर राजेश शिरवडकर ने कहा कि जितेंद्र सिंह लंबे समय से सामाजिक और जनहित के कार्यों में सक्रिय हैं। उनकी नियुक्ति से उत्तर पश्चिम जिला में संगठन को मजबूती मिलेगी और संगठन के विस्तार को भी गति मिलेगी। नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकताओं के सहयोग से संगठन की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए वे निरंतर कार्य करेंगे।

वसई में विवेकभाऊ पंडित और स्नेहा दुबे पंडित ने 3 नई 'राजमाता जिजाऊ' एस.टी. बसों का किया उद्घाटन

वसई। वसई पश्चिम स्थित पार नाका एस.टी. बस डिपो में तीन नई 'राजमाता जिजाऊ' एस.टी. बसों का उद्घाटन स्टेट लेवल ट्राइबल डेवलपमेंट रिव्यू कमिटी के चेयरमैन (मंत्री दर्जा) विवेकभाऊ पंडित एवं वसई विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने उत्साहपूर्ण माहौल में किया।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और बेहतर यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। नई बसों के शामिल होने से वसई क्षेत्र के यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और विश्वसनीय परिवहन सुविधा मिलेगी तथा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।

कार्यक्रम में शिवसेना पालघर जिला प्रमुख, भाजपा वसई-विरार शहर जिला महासचिव बिजेंद्र कुमार, भाजपा वसई-विरार माइनॉरिटी फ्रंट के जिला अध्यक्ष मैथ्यू कोलासो, नगरसेविका निम्मी निपुण दोशी, पिंकी राठौड़, वसई सिटी काउंसिल अध्यक्ष गीतांजलि दरीवाला, भाजपा जिला सचिव प्रवीण गावड़े, एसआईआर वसई विधानसभा प्रमुख मयंक शेठ, संतोष काकड़, राजेश राठौड़, पूर्व नगरसेवक छोटू आनंद, सुनील तंडालेकर, सुचिता शेट्टी, भूपेश राउत, अजय चौकेकर, नंदू पवार, नरेश पुलिपाठी, यशोधन ठाकुर,

प्रमिला गैर, पुंडलिक राठौड़, अविनाश चावंडे, कैलाश वैती, गजानन भोईर, साधना पाटिल सहित एस.टी. बस डिपो के चालक, परिचालक, कर्मचारी, नागरिक और बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नई 'राजमाता जिजाऊ' एस.टी. बसों को वसईकरों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक परिवहन सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। इस दौरान भविष्य में भी नागरिकों की सुविधा के लिए परिवहन सेवाओं के विस्तार और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही गई।

इनडीड ने अपनी पहली एआई एट वर्क ट्रैकर 2026 रिपोर्ट जारी की

पटना। इनडीड ने अपनी पहली एआई एट वर्क ट्रैकर 2026 रिपोर्ट जारी की है। भारत में 1,267 नियोक्ताओं और 2,541 कर्मचारियों पर आधारित इस सर्वे के अनुसार, 66 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे ए.आई. कौशल वाले नए टैलेंट को अधिक वेतन देते हैं, जबकि एआई से जुड़े कार्य कर रहे 54 प्रतिशत कर्मचारियों ने कहा कि उनका वेतन या तो स्थिर है या पिछले एक वर्ष में कम हुआ है।रिपोर्ट के अनुसार, 40 प्रतिशत से अधिक संगठन एआई कौशल वाले पदों के लिए 11 से 30 प्रतिशत अधिक वेतन देते हैं, जबकि 26 प्रतिशत संगठन 31 से 50 प्रतिशत तक अधिक वेतन की पेशकश करते हैं। इसके विपरीत, 36 प्रतिशत कर्मचारियों ने बताया कि उनके वेतन में कोई बदलाव नहीं हुआ और 18 प्रतिशत ने वेतन में कमी आने की बात कही। इनडीड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर शशि कुमार ने कहा कि संगठनों को नए एआई टैलेंट को आकर्षित करने के साथ-साथ अपने मौजूदा कर्मचारियों के कौशल विकास और उचित मूल्यांकन पर भी समान ध्यान देना होगा। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 40 प्रतिशत नियोक्ता एआई नियुक्तियों में पारंपरिक डिग्री के बजाय कौशल और सर्टिफिकेशन को प्राथमिकता देते हैं, जबकि केवल 9 प्रतिशत नियोक्ता अब भी केवल शैक्षणिक डिग्री को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा, 63 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में एआई से जुड़े पदों पर नियुक्तियां बढ़ी हैं, जबकि 47 प्रतिशत नियोक्ता भर्ती प्रक्रिया में पहले से ही एआई का उपयोग कर रहे हैं।

रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य में शिथिलता को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे थॉमस जोसेफ

बदलापुर । क्षेत्र में स्थित सेन्ट जेवीयर्स स्कूल के निदेशक थामस जोसेफ ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि शाहगंज-प्रयागराज मार्ग पर श्रीकृष्णा नगर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे 2-लेन रेल ओवरब्रिज (फ्ब्इ) के निर्माण कार्य में राज्य सेतु निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भारी शिथिलता बरती जा रही है। कुल 38 करोड़ रुपये की लागत से निमार्णाधीन ओवरब्रिज में बरती जा रही शिथिलता को संजीदगी से लेते हुए कार्य में तेजी कराए जाने की मांग को लेकर निदेशक थामस जोसेफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करनें का मन बना रहे हैं। इस सम्बन्ध में निदेशक थामस जोसेफ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , राष्ट्रपति तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भी रजिस्टर्ड पत्र भेजकर ओवरब्रिज का अविलंब निर्माण कराये जाने की मांग किया है। इस परियोजना पर लगभग ?38 करोड़ खर्च किए जा रहे है । यह एक 2-लेन (ळ८ङ्ग-छंल्ली) चौड़ा रेलवे ओवरब्रिज है। यह रेलवे क्रॉसिंग (फाटक संख्या 23) के दोनों तरफ एप्रोच रोड को जोड़ती है। श्रीकृष्णा नगर रेलवे फाटक पर लगने वाले भारी जाम से जनता, स्कूली बच्चों और मरीजों को मुक्ति दिलाना ईश्वर ब्रिज का मुख्य उद्देश्य है। गौरतलाप है कि 17 सितंबर 2024 से बदलापुर प्रयागराज में वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद करके रोड डायवर्ट किया गया है। इस ओवर ब्रिज का वर्चुअल शिलान्यास जनवरी 2024 में किया गया था। सेंट जेवियर स्कूल के निदेशक थॉमस जोसेफ ने प्रेस वार्ता में बताया कि ओवर ब्रिज के निर्माण में भारी शीतलता बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप प्रतिदिन वाहन संचालकों छात्राओं व्यापारियों सहित अन्य तपके के लोगों के सामने आवागमन को लेकर भारी समस्या बनी हुई है। सुबह शाम विद्यालय की बसों को लगभग 2022 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी प्रतिदिन तय करनी पड़ रही है । लगभग दो दर्जन से अधिक विद्यालय के सैकड़ो वाहनों तथा शाहगंज से प्रयागराज आने जाने वाली बसों को अतिरिक्त दूरी तय की करनी पड़ रही है। जिससे अतिरिक्त व्यय और समय दोनों का भारी नुकसान हो रहा है।

विश्व आईवीएफ दिवस की पूर्व संध्या पर आशीर्वाद हॉस्पिटल में खुशियों का उत्सव, सफल दंपतियों ने साझा की मातृत्व-पितृत्व की कहानी

डॉ. इम्तियाज अहमद

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। विश्व आईवीएफ दिवस की पूर्व संध्या पर पॉलीटेक्निक चौराहा स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल एवं आईवीएफ सेंटर में जागरूकता एवं उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आईवीएफ उपचार से सफल हुए दंपतियों ने अपने बच्चों के साथ केक काटकर खुशियां मनाईं तथा अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर बांझपन के प्रति जागरूकता बढ़ाने, आधुनिक आईवीएफ तकनीकों की जानकारी देने और उपचार से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम का सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब आईवीएफ उपचार के माध्यम से संतान प्राप्त करने वाले एक दंपति ने अपने स्वस्थ शिशु के साथ विश्व आईवीएफ दिवस का केक काटा। दंपति ने वर्षों के संघर्ष के बाद माता-पिता बनने की अपनी भावनात्मक यात्रा साझा करते हुए आशीर्वाद हॉस्पिटल की आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ. अंजू कनौजिया और उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत और उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर डॉ. अंजू कनौजिया ने कहा कि आईवीएफ केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि उन दंपतियों के लिए नई उम्मीद है जो संतान सुख से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि समय पर जांच, सही परामर्श और आधुनिक उपचार तकनीकों के माध्यम से अधिकांश निःसंतान दंपतियों का माता-पिता बनने का सपना साकार किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से बांझपन को सामाजिक कलंक न मानकर एक उपचार योग्य चिकित्सकीय स्थिति के रूप में देखने की अपील की।

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने महिला एवं पुरुष बांझपन, स्वस्थ जीवनशैली और आधुनिक उपचार पद्धतियों पर विस्तार से जानकारी दी। उपस्थित दंपतियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया और उन्हें उपचार संबंधी आवश्यक सुझाव दिए गए। कार्यक्रम के अंत में डॉ. विनोद कुमार ने अतिथियों, सफल आईवीएफ परिवारों, मीडिया प्रतिनिधियों और अस्पताल की टीम का आभार व्यक्त करते हुए जन-जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में आईवीएफ और बांझपन से जुड़े मिथकों को दूर कर लोगों को वैज्ञानिक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में कांग्रेस गटनेता अशरफ आजमी से सदिच्छा भेंट

मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) मुख्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गटनेता एवं वॉर्ड क्रमांक 165 के नगरसेवक अशरफ आजमी से शिष्टाचार एवं सदिच्छा भेंट की गई। इस अवसर पर क्षेत्र के विकास, नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं, जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों तथा सामाजिक कार्यों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। अशरफ आजमी ने जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। भेंट के दौरान समाजसेवक सुखबिंदर सिंह (लाला भाई) भी उपस्थित रहे। सभी ने पारस्परिक सहयोग एवं समाजहित में मिलकर कार्य करने के संकल्प को दोहराया। यह सदिच्छा भेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।

राहुल गांधी देश की छवि धूमिल करने में जुटे, संसद छोड़ सड़क की राजनीति कर रहे : सरवर सिद्दीकी

वाराणसी। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री सरवर सिद्दीकी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनके बयान और गतिविधियां देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विकास, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर लगातार काम कर रही हैं, लेकिन विपक्ष तथ्यात्मक बहस के बजाय भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है।

सरवर सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार कर

रहे हैं और विदेश यात्राओं के दौरान भी ऐसे बयान देते हैं, जिनसे भारत की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना का अधिकार सभी को है, किंतु आलोचना तथ्यों और राष्ट्रीय हितों के दायरे में होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ऐसे व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति दिखाई है जिन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सिद्दीकी ने कहा कि इस प्रकार के राजनीतिक संदेश समाज में गलत संकेत देते हैं और जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं।

प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए सरवर सिद्दीकी ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत बताते हुए कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा हो और सरकार चर्चा के लिए तैयार हो, तब राजनीतिक मतभेदों को संसद के भीतर उठाना अधिक उचित है। उन्होंने कहा कि सड़क पर टकराव की राजनीति लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय अनावश्यक विवादों को जन्म देती है। जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन के संबंध में उन्होंने दावा किया कि इसके पीछे विदेशी शक्तियों की भूमिका होने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे किसी इनपुट या साक्ष्य की पुष्टि होती है तो संबंधित जांच एजेंसियों को निष्पक्ष एवं व्यापक जांच कर सच्चाई देश के सामने लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े किसी भी मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।

सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है तथा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था, आधारभूत ढांचे और निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। ऐसे समय में विपक्ष को निराधार आरोपों के बजाय रचनात्मक राजनीति और जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक संवाद करना चाहिए।

अंधेरी में युवासेना की संगठनात्मक बैठक, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर दिया गया जोर

मुंबई। शिवसेना युवासेना (उद्धव) अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र की ओर से गुरुवार देर शाम अंधेरी (पूर्व) के पारसीवाड़ा स्थित शाखा क्रमांक-83 में संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को नई गति और दिशा देने के साथ बूथ एवं वार्ड स्तर तक उसे मजबूत बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए युवासेना (उद्धव) अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विभाग अधिकारी अमेय रमेश लटके ने कहा कि पार्टी नेतृत्व की मंशा है कि आने वाले दिनों में विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ और वार्ड तक संगठन को सशक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी और संगठन को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी कार्यकताओं को सौंपी गई है, उस पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरा उतरना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी नेतृत्व का पूरा सहयोग कार्यकताओं को मिल रहा है। बैठक के दौरान युवासेना के कई पदाधिकारियों ने संगठन विस्तार, कार्यकताओं की सक्रिय भागीदारी और जनसंपर्क बढ़ाने को लेकर अपने सुझाव भी रखे। इस अवसर पर उप विभाग अधिकारी संदेश मोरे, जयेंद्र कूटे, अनिकेत छाछड़, शाखा अधिकारी मनीष नेरुलकर, समन्वयक प्रलेश सावंत, बैभव पवार सहित बड़ी संख्या में युवासेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

श्री रामजानकी मंदिर के विकास को मिली रफ्तार, 1.34 करोड़ की परियोजना का गिरीश चंद्र यादव ने किया शिलान्यास

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नगर पालिका परिषद जौनपुर स्थित श्री रामजानकी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मंदिर परिसर के विकास के लिए वन्दन योजना के तहत 1 करोड़ 34 लाख रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश गिरीश चंद्र यादव ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से भूमि पूजन कर शिलापट्ट का अनावरण किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के धार्मिक स्थलों का लगातार विकास कराया जा रहा है। वन्दन योजना के अंतर्गत श्री रामजानकी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, परिसर का सौंदर्यीकरण और आवश्यक अवस्थापना कार्य कराए जाएंगे। इससे जौनपुर में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह मंदिर जौनपुर के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। परियोजना पूर्ण होने के बाद मंदिर परिसर को नया स्वरूप मिलेगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष दक्षिणी कमलेश निषाद ने की, जबकि संचालन सभासद नंदलाल यादव ने किया। इस अवसर पर सुनीत प्रकाश श्रीवास्तव पिंटू, अतुल सिंह काका, अरुण सिंह, कमल सिंह, गिरीश कुमार सिंह पप्पू, अतुल श्रीवास्तव, गौरव जायसवाल, मनीष श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंघानिया, बसंत प्रजापति, संतोष मौर्य, माधुरी गुप्ता, मिलन श्रीवास्तव, संदीप, सुप्रतीक गुप्ता समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

किया साइरोस ईवी 13.49 लाख रुपये की आकर्षक कीमत पर लॉन्च

मुंबई। भारत की प्रमुख मास-प्रीमियम वाहन निमार्ताओं में से एक, किआ इंडिया ने आज भारत में निर्मित अपने दूसरे मास-मार्केट इलेक्ट्रिक वाहन, किआ साइरोस ईवी को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरूआती कीमत 42 'ह वैरिएंट के लिए 13.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और 51.4 'ह एक्सटेंडेड रेंज वैरिएंट के लिए 16.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अधिक सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, किआ ने इस कीमत के साथ उद्योग के सबसे मजबूत ओनरशिप प्रस्?ताव पेश किए हैं, जिनमें उद्योग का सर्वश्रेष्ठ अश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम, बैटरी-ऐज-अ-सर्विस (बीएएएस) और लाइफटाइम हाई-वोल्टेज बैटरी वारंटी शामिल हैं। ये सुविधाएं इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने की प्रक्रिया को अधिक किफायती, सुरक्षित और चिंतामुक्त बनाती हैं। किआ साइरोस ईवी की बिक्री देश भर की किआ डीलरशिप्स पर 30 जुलाई 2026 से शुरू होगी। साइरोस ईवी किआ इंडिया के इस विश्वास को दशार्ती है कि ईवी को अपनाने की गति बढ़ाने के लिए सिर्फ एक मजबूत प्रोडक्ट से बढ़कर, ओनरशिप के पूरे सफर में वास्तविक आत्मविश्वास और वैल्यू की आवश्यकता होती है। भारत में निर्मित, साइरोस ईवी आधुनिक डिजाइन और सेगमेंट-लीडिंग परफॉर्मेंस को अपनी श्रेणी के सबसे व्यापक ईवी ओनरशिप इकोसिस्टम के भरोसे के साथ जोड़ती है।

कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के जन्मदिवस पर 25 जुलाई को 'संकल्प दिवस' का आयोजन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री (कारागार विभाग) दारा सिंह चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर 25 जुलाई 2026 को चौहान समाज द्वारा संकल्प दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रातः 11:00 बजे मार्स ऑडिटोरियम, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक होंगे। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्र सरकार के मंत्री पंकज चौधरी, विभिन्न सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि तथा भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इस अवसर पर चौहान समाज के विभिन्न जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में समाज की एकता, सामाजिक उत्थान, संगठन को मजबूत करने तथा समाज के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार, दारा सिंह चौहान के नेतृत्व में चौहान समाज को एकजुट करने और आगामी समय की सामाजिक एवं राजनीतिक दिशा पर भी चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में समाज के लोगों के शामिल होने की संभावना है।

स्वर्णिम पड़ाव पर कालीन उद्योग, भदोही बनेगा वैश्विक कारोबार का केंद्र

भदोही। भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग की वैश्विक पहचान को नई ऊंचाई देने वाले 50वें (गोल्डन जुबिली) इंडिया कारपेट एक्सपो-2026 की तैयारियां अब निर्णायक दौर में पहुंच गई हैं। 4 से 6 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन को अब तक का सबसे भव्य, सुव्यवस्थित और गरिमामय बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कारपेट एक्सपो मार्ट, कारपेट सिटी भदोही में दूसरी तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के उपाध्यक्ष असलम महबूब ने की। बैठक में एक्सपो की सुरक्षा, आगंतुक सुविधाएं, प्रदर्शनी प्रबंधन, खरीदारों के स्वागत, लॉजिस्टिक व्यवस्था, प्रचार-प्रसार तथा विभिन्न प्रशासनिक तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। सभी समितियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं के अनुरूप संपन्न हो सके। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 50वां इंडिया कारपेट एक्सपो केवल एक व्यापारिक मेला नहीं, बल्कि भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग की आधी सदी की उपलब्धियों, उत्कृष्ट शिल्प, परंपरा, नवाचार और वैश्विक प्रतिष्ठा का स्वर्णिम उत्सव है। यह आयोजन दुनिया के प्रमुख खरीदारों, निर्यातकों, आयातकों, डिजाइनरों और निमार्ताओं को एक ही मंच पर लाएगा, जिससे नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे और भारतीय कालीन उद्योग के लिए निर्यात के नए द्वार खुलेंगे। सीईपीसी पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि गोल्डन जुबिली संस्करण भारतीय कालीन उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान देने के साथ-साथ 'मेड इन इंडिया' हस्तनिर्मित कालीनों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को और मजबूत करेगा।

विश्व क्लेफ्ट जागरूकता दिवस पर स्माइल ट्रेन इंडिया की जागरूकता पहल

मुंबई। विश्व क्लेफ्ट जागरूकता दिवस पर स्माइल ट्रेन इंडिया की जागरूकता पहल ; 8 लाख से अधिक मुफ्त क्लेफ्ट सर्जरी पूरी की, समय पर पहचान पर दिया जोर

भारत में एक बड़ी सर्जिकल उपलब्धि हासिल करते हुए, स्माइल ट्रेन इंडिया के बिहार में मौजूद 3 सक्रिय साझेदार अस्पतालों के नेटवर्क ने अब तक 34,000 से ज्यादा बच्चों की मुफ्त क्लेफ्ट सर्जरी में मदद की है। संस्था अब इलाज के साथ-साथ क्लेफ्ट की जल्दी पहचान, लोगों में जागरूकता बढ़ाने और समय पर उपचार की जरूरत पर भी ध्यान दे रही है। पटना, जुलाई 2026: हर साल 20 जुलाई को दुनिया भर में विश्व क्लेफ्ट जागरूकता दिवस (वर्ल्ड क्लेफ्ट अवेयरनेस डे) मनाया जाता है। इस दिवस की शुरूआत वर्ष 2025 में स्माइल ट्रेन ने की थी, ताकि क्लेफ्ट (कटे होंठ और तालू) के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े और इस विषय को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनाया जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्लेफ्ट के साथ जन्म लेने वाले हर बच्चे को समय पर और पूरा इलाज मिल सके। इस वर्ष क्लेफ्ट उपचार के क्षेत्र में काम करने वाली देश की अग्रणी गैर-लाभकारी संस्था स्माइल ट्रेन इंडिया ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2000 से अब तक संस्था ने पूरे भारत में 8 लाख से अधिक बच्चों की मुफ्त क्लेफ्ट

सर्जरी कराने में मदद की है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद अब संस्था का मुख्य ध्यान लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर है, ताकि क्लेफ्ट के साथ जन्म लेने वाले हर बच्चे की समय रहते पहचान हो सके और उसे सही समय पर इलाज मिल सके, जिससे वह स्वस्थ और बेहतर जीवन जी सके। भारत में हर साल लगभग 25,000 बच्चे क्लेफ्ट (कटे होंठ या कटे तालू) के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन जागरूकता की कमी, गलत धारणाओं, गलत जानकारी और सामाजिक भेदभाव के कारण कई बच्चों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इलाज में देरी होने से बच्चों को दूध पीने और खाना खाने में परेशानी, कुपोषण, बोलने और सुनने में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, उन्हें आगे चलकर सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। समय पर क्लेफ्ट की पहचान और सही समय पर सर्जरी कराने से बच्चों का इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है और उन्हें जरूरी सभी चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सकता है। विश्व क्लेफ्ट जागरूकता दिवस का उद्देश्य लोगों को क्लेफ्ट के बारे में जागरूक करना, इससे जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि क्लेफ्ट के साथ जन्म लेने वाले हर बच्चे को समय पर सही इलाज मिल सके।

विश्व क्लेफ्ट जागरूकता दिवस के अवसर पर स्माइल ट्रेन इंडिया ने माता-पिता, देखभाल करने वालों, स्वास्थ्यकर्मियों, नीति-निमार्ताओं, मीडिया और समाज के सभी लोगों से अपील की है कि वे क्लेफ्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, समय पर पहचान और इलाज को बढ़ावा दे इससे जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। मुफ्त क्लेफ्ट उपचार या अधिक जानकारी के लिए स्माइल ट्रेन इंडिया की टोल-फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क करें: 1800 103 8301।

मरकजी सीरत कमेटी जौनपुर चुनाव का ऐलान, 25 जुलाई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मरकजी सीरत कमेटी जौनपुर के चुनाव को लेकर चुनाव समिति ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। समिति के अनुसार चुनाव प्रक्रिया 25 जुलाई 2026 से शुरू होगी और 2 अगस्त 2026 को मतदान कराया जाएगा। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की तैयारी की गई है। जारी कार्यक्रम के मुताबिक 25 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नामांकन पत्रों का वितरण किया जाएगा। वहीं 26 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नामांकन पत्र जमा करने और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया होगी। 27 जुलाई को शाम 6 बजे तक नामांकन वापसी का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक अंतिम प्रत्याशी सूची और मतदाता सूची जारी की जाएगी।

चुनाव में मतदान 2 अगस्त 2026 (रविवार) को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना कर विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। बताया गया कि यह चुनाव अंजुमनों, फन-ए-सिपाहगरी के अखाड़ों, सजावट कमेटियों तथा ईद मिलादुन्नबी के जलसे और जुलूस में शामिल प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। चुनाव समिति ने सभी सदस्यों से निर्धारित समय का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। मरकजी सीरत कमेटी के चुनाव प्रभारी हाजी अब्दुल अहद मुन्ने ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी।

क्रिएलिटी और वॉल 3D ने 3D प्रिंटिंग 'एक्सपीरिएंशियल' स्टोर लॉन्च किया

मुंबई। थ्रीडी प्रिंटिंग के क्षेत्र में दुनिया की दिग्गज कंपनी क्रिएलिटी और भारत की प्रमुख थ्रीडी प्रिंटिंग कंपनी वॉल थ्रीडी ने पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित कोपा मॉल में शहर का पहला 'एक्सपीरिएंशियल' थ्रीड प्रिंटिंग रिटेल स्टोर लॉन्च किया है। इस स्टोर में ग्राहक लाइव थ्रीडी प्रिंटिंग होते हुए देख सकते हैं और यह अनुभव कर सकते हैं कि कैसे डिजिटल कॉन्सेप्ट्स को असल चीजों (ऑब्जेक्ट्स) में बदला जाता है—वह भी रियल-टाइम में। यह लॉन्च क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेस, हॉबी रखने वालों और टेक्नोलॉजी के शौकीनों के लिए थ्रीडी प्रिंटिंग को ज्यादा आसान, इंटरैक्टिव और दिलचस्प बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही, यह २९ मई, २०२६ को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद, दुनिया भर में अपनी ऑफलाइन रिटेल मौजूदगी को बढ़ाने के लिए क्रिएलिटी के लगातार निवेश को भी दिखाता है। पुणे के मशहूर लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन, कोपा मॉल की दूसरी मंज़िल पर मौजूद यह स्टोर थ्रीडी प्रिंटिंग का एक प्रैक्टिकल और इंटरैक्टिव अनुभव देता है। यहाँ चालू हालत में क्रिएलिटी प्रिंटर और अलग-अलग तरह के फिलामेंट कलर्स रखे गए हैं। वॉल थ्रीडी के एक्सपर्ट्स विज़िटर्स को थ्रीडी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को समझने और इस्तेमाल करने में मदद करने के लिए मौजूद रहते हैं। वॉल थ्रीडी के सीईओ राहुल चंडालिया ने कहा, ₹हम क्रिएलिटी के साथ मिलकर कोपा मॉल में अपना पहला थ्रीडी प्रिंटिंग रिटेल स्टोर शुरू करने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इस स्टोर के जरिए हमारा मकसद थ्रीडी प्रिंटिंग को लोगों के करीब लाना और एक ऐसी जगह बनाना है जहाँ वे असल ज़िंदगी में इस टेक्नोलॉजी को देख, समझ और अनुभव कर सकें।

कैंटाबिल ने नए स्टोर के साथ महाराष्ट्र में अपनी उपस्थिति मजबूत की

मुंबई। भारत की प्रमुख परिधान निमार्ता और रिटेलर कंपनियों में से एक, कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड ने भिवंडी में अपना 28वां स्टोर लॉन्च करके महाराष्ट्र में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर लिया है। 910 वर्ग फुट में फैला यह नया ब्रांड स्टोर फर्स्ट फ्लोर, भूमि वर्ल्ड मॉल, भिवंडी स्थित है, जो ब्रांड के विस्तार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पुरुषों के लिए कैजुअल, पार्टी और फॉर्मल वियर के साथ-साथ ट्रेंडिंग एक्सेसरीज की विस्तृत रेंज पेश करते हुए, कैंटाबिल ने शॉपिंग के अनुभव को एक नया आयाम दिया है। इसके साथ ही कैंटाबिल ने फैशन उद्योग में एक अग्रणी ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। इस शानदार लॉन्च पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड के निदेशक श्री दीपक बंसल ने कहा, ₹हम भिवंडी में पुरुषों के परिधानों और एक्सेसरीज का अपना नया एक्सक्लूसिव स्टोर शुरू करते हुए बेहद उत्साहित हैं। मिड-प्रीमियम सेगमेंट में कैंटाबिल को ग्राहकों से हमेशा जबरदस्त प्यार और सराहना मिली है। हमारा यह नया स्टोर पुरुषों के लिए आधुनिक और ट्रेंडी फैशन कपड़ों की विस्तृत श्रृंखला पेश करेगा। पूरे भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ, हम आने वाले वर्षों में अपने रिटेल नेटवर्क को और विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कैंटाबिल लगातार बदलते फैशन के दौर को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट स्टाइल और प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े पेश करता आ रहा है।

आंध्र प्रदेश सरकार और पंजाब नेशनल बैंक ने अमरावती क्वांटम वैली में भारत का पहला बैंक-संचालित क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

मुंबई। उभरती प्रौद्योगिकियों (इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज) के माध्यम से भारत के भावी बैंकिंग तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार और पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने आज अमरावती क्वांटम वैली (एक्यूवी) में 'पीएनबी क्वांटम फाइनेंस हब' की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और पीएनबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अशोक चंद्र की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया, जो भारत के बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान, प्रतिभा विकास तथा अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार और पीएनबी की साझा प्रतिबद्धता को दोहराता है। इस अवसर पर, अशोक चंद्र ने 'पीएनबी क्वांटम फाइनेंस हब' का उद्घाटन किया, जिससे पीएनबी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक समर्पित क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने हेतु किसी राज्य सरकार के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। यह हब एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा जो बैंकिंग सेवाओं में सुधार, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने, धोखाधड़ी का पता लगाने

की प्रणाली को बेहतर बनाने, व्यावसायिक परिचालन को अनुकूलित करने, ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और भविष्य के लिए सुरक्षित डिजिटल वित्तीय प्रणालियों का निर्माण करने वाले व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और प्रौद्योगिकी भागीदारों को एक साथ लाएगा। बैंकिंग क्षेत्र तीव्र डिजिटल परिवर्तन का साक्षी बन रहा है, जिसके साथ तेजी से जटिल होते साइबर खतरे, बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के प्रयास और निरंतर विकसित होती सुरक्षा चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसके साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में हो रहे विकास वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं। जहां एक ओर ये प्रौद्योगिकियां कार्यकुशलता, ग्राहक सेवाओं और जोखिम प्रबंधन में सुधार के व्यापक अवसर प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर ये बैंकों से भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहने और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचे को अपनाने की भी मांग करती हैं। पीएनबी क्वांटम फाइनेंस हब अगली पीढ़ी के ऐसे बैंकिंग समाधानों के विकास, परीक्षण और उन्हें अपनाने में सक्षम बनाएगा जो सुरक्षित, बुद्धिमत्तापूर्ण और भविष्य के लिए तैयार हों। यह पहल सहयोगात्मक अनुसंधान का भी समर्थन करेगी, स्टार्टअप्स के बीच नवाचार को प्रोत्साहित करेगी, उद्योग-शिक्षा जगत की भागीदारी को बढ़ावा देगी और एक कुशल कार्यबल का निर्माण करेगी जो वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को गति देने में सक्षम हो।

दूसरों को न्याय दिलाने वाले खुद 'अन्याय' की राह पर चलने को मजबूर

0-भदोही जिला न्यायालय परिसर के अधिवक्ता चैंबर मार्ग की बदहाली, हल्की बारिश में सड़क बनी तालाब; रोजाना 200 से अधिक अधिवक्ता, वादकारी और कर्मचारी दलदल पार कर पहुंचते हैं कोर्ट

-सुरेश गांधी

भदोही। जहां से न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है, वहीं तक पहुंचने का रास्ता खुद अन्याय की कहानी बयां कर रहा है। भदोही जिला न्यायालय परिसर स्थित अधिवक्ताओं के चैंबर तक जाने वाली सड़क की बदहाली ऐसी है कि मामूली बारिश होते ही पूरा मार्ग कीचड़ और पानी से भरकर तालाब में तब्दील हो जाता है। ऐसे में प्रतिदिन 200 से अधिक अधिवक्ताओं के साथ सैकड़ों वादकारियों और न्यायालय कर्मचारियों को इसी दलदल से

होकर अदालत तक पहुंचना पड़ता है। बारिश के बाद सड़क पर कई-कई इंच पानी जमा हो जाता है। जगह-जगह बने गड्ढों में कीचड़ भर जाने से राहगीरों को यह भी पता नहीं चलता कि पैर कहां पड़ रहा है। कई बार अधिवक्ता फिसलने से बचते-बचते निकलते हैं, जबकि मुवक्किलों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह रास्ता किसी परीक्षा से कम नहीं रह जाता। विडंबना यह है कि रोजाना संविधान, कानून और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में बहस करने वाले अधिवक्ता स्वयं मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। काले कोट में कीचड़ से सने जूते और पैंट के साथ अदालत पहुंचना उनकी मजबूरी बन चुकी है। न्यायालय की गरिमा से जुड़ा यह दृश्य लंबे समय से जिम्मेदार विभागों की उदासीनता की गवाही दे रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस सड़क की दुर्दशा को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकला। हर बरसात में यही स्थिति बनती है और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़क पूरी तरह जलमग्न हो जाती है। यह केवल एक सड़क की समस्या नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था से जुड़े पूरे वातावरण का प्रश्न है। जिस परिसर में प्रतिदिन सैकड़ों लोग न्याय की उम्मीद लेकर आते हों, वहां की मूलभूत सुविधाएं इस हाल में होना गंभीर चिंता का विषय है। न्यायालय परिसर की सड़क यदि दलदल में बदल जाए तो यह व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से तत्काल सड़क की मरम्मत, पक्की जलनिकासी व्यवस्था तथा स्थायी समाधान की मांग की है, ताकि न्यायालय आने वाले अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादकारियों को इस परेशानी से निजात मिल सके।

विडंबना यह है कि जो अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाने के लिए अदालत में खड़े होते हैं, उन्हें स्वयं रोज अन्यायपूर्ण परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। न्यायालय परिसर की यह बदहाली तत्काल सुधारे जाने की मांग करती है।